महोदय, आज जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथों में हथियार हैं। सुबह भी इस सदन में एक मुद्दा, एक विषय लाया गया। आज इस देश में जो मुश्किलें पैदा हुई हैं, देश में जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महँगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अगर सरकार समय रहते नहीं चेती, तो हालात बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर सकते हैं। अब तक तो सांसदों पर हमला होता था। अब संसद पर भी हमला होने लगा है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : समाप्त कीजिए।

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप : बाहर के लोग आज सवाल उठा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश के 120-122 करोड़ लोगों के हितों के बारे में सोचिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाइए और इस देश के जो वीकर सैक्शंस के लोग हैं, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे कमजोर किसान हों, इनके हित के लिए अपने इस बजट में अलग से बजट की व्यवस्था कीजिए, ताकि ये लोग भी अपने जीवन को सुखद बना सकें, सुखी जीवन जी सकें **(समय की घंटी)**।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : The House is adjourned to meet at 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at six minutes past one of the clock.

The House re-assembled, after lunch, at two minutes past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.

THE BUDGET (GENGERAL) 2012-13

श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँगा और आपने मुझे जनरल बजट पर डिस्कशन में अपने विचार रखने के लिए जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा।

उपसभाध्यक्ष जी, पूरी दुनिया में economic situation बड़ी खराब स्थिति से गुजर रही है। अमेरिका, जो कि एक economic power के रूप में गिना जाता है, उसकी अपनी economy की स्थिति ठीक नहीं है। यूरो ज़ोन के सभी देशों की economy डावाँडोल है और यह सच है कि जब वहाँ स्लो डाउन होगा, तो उसका असर हमारे देश की economy पर भी आने वाला है। हमारे एक्सपोर्ट्स पर उसका असर आ सकता है, हमारे यहाँ प्रॉडक्शन पर उसका असर आ सकता है और लेबर पर भी उसका असर पड़ सकता है। ऐसी समस्या से गुजरते हुए भी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस साल का जो बजट पेश किया है, वह वाकई एक तार के ऊपर की कसरत थी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया है और इसीलिए मैं उन्हें सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा।

सर, हमारे देश के ऊपर बाहर की economy का यह जो असर पड़ रहा था, उससे हमारे करेंट अकाउंट में डिफिसिट की प्रॉब्लम का निर्माण हो रहा था, हमारे देश का जो चलन है, जो रुपए की कीमत घट रही थी, हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ था और फिस्कल डिफिसिट की प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी थी। मैं करीब दो महीने पहले जब वित्त मंत्री जी से एक कमेटी की मीटिंग में मिला था, तब मैंने उनसे यह भी पूछा था कि महोदय, आपको रात में नींद कैसे आती है?

[श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन]

क्योंकि, इस स्थिति से गुजरना बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हम गुजर रहे हैं। परंतु, आपके अनुभव से, आपके नेतृत्व के अंदर हम इससे बाहर निकलेंगे, यह विश्वास भी मुझे है। लेकिन, urgently कुछ स्टेप्स उठाने की जरूरत है, जिनकी वजह से हम अपने आपको इससे अनभिज्ञ रख सकें, इसको अछूता रख सकें।

महोदय, यूरो जोन की इतनी बिगड़ी हुई हालत है कि यूरो टिकेगा या नहीं टिकेगा। ऐसी स्थिति में हमें अछूता रहना असंभव था, परंतु इन सब conditions के रहते हुए आदरणीय वित्त महोदय ने और उनके सभी finance के साथियों ने मिल कर देश को इस स्थिति से उबारा, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और जो बजट उन्होंने पेश किया है, मैं उसकी ओर मुड़ता हूँ।

महोदय, हमारा देश खेती प्रधान देश है। जब तक खेती की उन्नति नहीं होगी, तब तक हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। यह विचार इस शासन के बिल्कुल दिल में बैठ गया है, इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया जा रहा है। उसकी तरफ thrust देने के लिए जो एलोकेशंस किए गए हैं, वे अच्छे हैं, जिनसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण की उपलब्धि होगी, जब ब्याज पर उपलब्धि होगी, उनको अच्छे बीज मिलेंगे, उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था होगी, उनके खेत के लिए सिंचन की व्यवस्था होगी, इस दृष्टिकोण से जो कदम उठाए गए हैं, ये वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि सिंचन के मद में हमारा जो एलोकेशन है, उससे बड़े-बड़े डैम्स बनने में तो काफी वर्ष लग जाएंगे, परंतु अगर हम जगह-जगह पर पानी को रोक कर और छोटे-छोटे किसानों को, जिनकी आसपास में 100-200 एकड़ जमीन हो, उनको अगर इस तरह से पानी की उपलब्धि करा सकें, तो उसके परिणाम अच्छे होंगे। यह बहुत छोटे से duration में कम खर्च में पूर्ण हो सकता है।

महोदय, मैंने अपने जिले के अंदर, मेरे पड़ोस के जिले में मेरे मित्र ने इसी प्रकार से नाला बंडिंग्स किए, जिसमें हमने नालों को 20-20, 25-25 फीट तक गहरा किया, उसको चौड़ा भी किया, उनको एक-एक किलोमीटर तक, दो-दो किलोमीटर लम्बाई तक चौड़ा किया। उसमें खर्च तो बहुत ज्यादा नहीं आया, परंतु आज भी, यानी मार्च के महीने में भी, उसके अंदर 15 फीट से 20 फीट तक पानी उपलब्ध है और उसकी वजह से पड़ोस के जो किसान हैं, उनको पानी मिल रहा है। वे इससे दोबारा भी लाभ उठा सकते हैं, यानी रबी के सीजन में भी और खरीफ के सीजन में भी। इससे उनकी इनकम बढ़ गई है।

महोदय, हमारा thrust अगर irrigation की तरफ है, तो मैं कहूंगा कि किसान की इनकम बढ़ाने के लिए drip irrigation सबसे बड़ा माध्यम है। अगर drip लगा जाए, तो इससे पानी का उपभोग भी कम होता है और उत्पादन भी करीब-करीब तीन गुना बढ़ जाता है। हमारे यहां के किसान अगर rain-fed के ऊपर कपास बोता है, तो कपास की प्रति एकड़ उपज चार-पांच क्विटल से अधिक नहीं होती है और इसी को ड्रिप के ऊपर वह लगाता है, तो वह प्रति एकड़ 20 से 25 क्विटल का yield लेता है। इससे उसकी माली हालत भी सुधरती है और देश का उत्पादन भी बढ़ता है। इसीलिए, drip irrigation के ऊपर अधिक से अधिक एलोकेशन होना चाहिए, परंतु हम उतना एलोकेशन नहीं दे पा रहे हैं। एलोकेशन है, लेकिन हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हम इसमें सब्सिडी देकर इसको बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं, ताकि किसान इसके महत्व को समझे और इसको समझ कर इसको अपनाए। यदि यह महंगा पड़ेगा, तो वह इसको नहीं अपना पाएगा और उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। इसीलिए, हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं। परंतु, महोदय, हम उसके लिए एलोकेशन कितना छोटा रखते हैं। मैं अपनी तहसील की बात कहूंगा कि हमारे जिले के अंदर 15 तहसील हैं, उनमें से हर तहसील को 800-800 एकड़ के लिए drip irrigation का एलोकेशन कर सकें, इतना एलोकेशन हमें केन्द्र सरकार की ओर से मिला है। अब 800 एकड़ के लिए ही एलोकेशन मिला है, लेकिन मेरी एक ही तहसील ऐसी है, जिसके अंदर 15,000 एकड़ की डिमांड है। अब 1,500 एकड़ की डिमांड हो और अगर हम 800 एकड़ को एलोकेशन देंगे, तो 20 साल तक भी किसान को drip मिलने वाला नहीं है। इस तरह से न तो उसका उत्पादन बढ़ेगा और न राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा।

इसलिए अगर हमें राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने पर thrust देना है, हमें सम्पूर्ण होना है, हमें एक्सपोर्ट भी करना है और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, तो ड्रिप के ऊपर और अधिक allocation करने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारा शासन किसानों को सस्ता ऋण देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने 4 परसेंट के ऊपर 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपये का इस साल allocation किया है कि हम लोग इतना कर्ज बॉटेंगे, उसे 4 परसेंट पर दिलाएँगे। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, परन्तु हम लोग इससे भी आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मैं जिस स्टेट से आता हूँ, उस महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हमारी महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए एक लाख तक के ऋण को इंटरेस्ट फ्री रखा है। जो short duration crop loan होता है, उसके लिए एक लाख तक के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके अलावा, तीन लाख रुपये तक की जो सीमा रखी गयी है, उनकी कोशिश उसे भी पाँच लाख रुपये तक बढ़ाने की है। महोदय, तीन लाख के ऋण को सिर्फ दो परसेंट इंटरेस्ट पर उपलब्ध कराना महाराष्ट्र गवर्नमैंट के लिए पॉसिबल है, लेकिन वह केन्द्र शासन के लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे देश की सरकार इस तरफ भी ध्यान दे कि इसको महाराष्ट्र सरकार कैसे कर रही है। अगर वह अपना हिस्सा उठा रही है, तो दूसरे राज्य भी उसका अनुकरण करें और अगर वे नहीं कर पाएँ, तो मैं केन्द्र सरकार से यह अपेक्षा करता हूँ कि उसको एक प्रकार से और भी कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा देना चाहिए। एक लाख तक के ऋण तो बिल्कुल माफ होने चाहिए, ताकि किसान अपनी हालत सुधार सके, क्योंकि वह बहुत छोटा आदमी है, उसकी इनकम भी छोटी है, इसलिए उसे मदद की खास जरूरत है और इसीलिए तो हम subsidise कर रहे हैं। अगर आप subsidise कर रहे हैं, तो उसे पूरा कीजिए ताकि उसका लाभ उसको मिल सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्वास्थ्य आदि बातों पर काफी अच्छा thrust दिया गया है। इसमें रूरल डेवलपमेंट के लिए thrust दिया गया है और इसीलिए हमारी दिशा बिल्कुल सही है, परन्तु यह दिशा बड़ी स्लो है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए पैसों का सवाल है और हमारे पास आखिर जितना होगा, उतना ही हमें देना होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी साढ़े चार लाख करोड़ रुपये तक का ऋण उठा कर इसको पूरा कर रहे हैं। ऋण उठाने की भी हमारी लिमिट है, परन्तु मैं यह बात भी कहूँगा कि हमें दूसरे की तरफ भी देखना होगा। आज हम अमेरिकन इकॉनमी की तरफ देखें कि उनका सालाना बजट कितने ट्रिलियन का है। हालांकि उनका 15 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट इकट्ठा हो गया है, फिर भी वे पूरी दुनिया के चौधरी बन कर बैठे हुए हैं। उनका डॉलर devalue नहीं होता, हमारा रुपया क्यों devalue हो जाता है? आखिर क्या कारण हैं, वे किस वजह से मजबूत हैं? इन बातों को भी हमें देखना होना और उस दृष्टिकोण से हमें अपने कदम उठाने होंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट दे रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यह भी देखना चाहिए। एक तो पूरे देश में सब तरफ रेल का जाल फैल जाए और दूसरा यह कि हमारे ports अच्छे हो, हमारी roads अच्छी हो।

महोदय, आने वाले समय में हमें ports के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आज चेन्नई से सिंगापुर जहाज के कंटेनर्स भेजने हो, तो जो चीज़ वहाँ जाती है, वह जितनी लागत से वहाँ पहुँचती है, उससे कहीं ज्यादा लागत से वह चेन्नई से मुम्बई पहुँचती है, क्योंकि वहाँ के लिए उससे कहीं ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वह चीज़ वहाँ या तो सड़क मार्ग से जाएगी या रेल मार्ग से जाएगी। जब वह चीज़ वहाँ जाएगी अगर उसके लिए रेल का एक रैक होगा, तो उस पर केवल सौ कंटेनर्स आ पाएँगे, जबकि जहाज के अंदर सैंकड़ों कंटेनर्स जा सकेंगे और उसकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी। इसीलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने कदम उठाते समय इस दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब रेलवे की बात आती है। अभी रेलवे ने अपने बजट में अपेक्षा की कि उसे 45 हजार करोड़ रुपये शासन की तरफ से मिलने की अपेक्षा थी, लेकिन शासन ने उनको 20 हजार करोड़ उपलब्ध करा दिए। अब 20 हजार करोड़ रुपये में वे कितनी डेवलपमेंट कर पाएँगे और कितनी सेफ्टी दे पाएँगे? महोदय, अगर रेलवे को अपना

[श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन]

इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, तो एक तो वह खुद पैसे खड़े करे, या तो वह ऐसे करे या फिर शासन दे। वैसे करेंगे, तो वे उतना ब्याज दे नहीं पाएँगे, क्योंकि उतना उत्पादन होना चाहिए। तो, खुद के पैसे खड़े करने के लिए जो प्रयत्न किए गये थे, उनमें अड़चनें पैदा हो गई, परन्तु शासन अगर अपनी तरफ से 20 करोड़ रुपये देने की बाजय उनका allocation बढ़ा दें, तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है। अगर वह अच्छा होगा, तो हमारा देश उन्नति की तरफ ज्यादा स्पीड के साथ जा सकेगा। रोड़ अच्छे होंगे तो हमारा जो यातायात है, वह अधिक सुलभ हो सकेगा और पोर्ट अच्छे होंगे, तभी हम एक्सपोर्ट के लिए भी अपने आपको काफी बना पाएंगे

उपसभाध्यक्ष महोदय, एयरपोर्ट होने चाहिए। यह हमारी तरक्की की एक निशानी है। मैं कहूंगा कि परसों ही अभी हमारे गांव के अंदर महामहिम राष्ट्रपति जी ने उदघाटन किया। अभी फेज-1 ही पूरा हुआ है, दूसरे का काम शुरू होने वाला है। उपासभाध्यक्ष महोदय, इसमें जो भी लागत आई है, क्यों उसका रिटर्न हमें मिलने वाला है? उस एयरपोर्ट का क्या उपयोग होगा, कितना वह चलेगा? क्योंकि, मैं देख रहा हूं कि नासिक का एयरपोर्ट पहले चला, फिर बन्द हो गया। हमारे जलगांव की भी स्थिति हो जाएगी कि यह एयरपोर्ट बन तो गया, परन्तु वहां न तो एयर ट्रेफिक मिल रहा है, न कार्गो मिल रहा है और जो पैसा हमने इंवेस्ट किया उसका रिटर्न भी नहीं मिल रहा है हम रिटर्न की बात सोचते हैं, तभी हम काम करते हैं। किसान के पास अपनी खेती के अंदर कुंआ है, पानी है, परन्तु वह पानी का उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास बिजली की लाइन नहीं है। बिजली की लाइन के लिए जब हम जाते हैं तो वह काफी डिमांड करता है। उसका कहना है कि इसका जो रेवेन्यू रिटर्न है, वह पूरा नहीं मिलता इसलिए हम वहां तक नहीं आ पाएंगे, जब तक कि उतनी डिमांड नहीं होगी। अगर उतनी डिमांड हो जाएगी तो हमारे पास सप्लाई नहीं होगी। इस प्रकार इतना पानी होने के बाद भी वह किसान इसका उपयोग नहीं कर पाता।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज दुनिया के अंदर नए-नए इंवेंशन आ रहे हैं। आजकल सोलर पम्प निकले हैं। उसके लिए लाइन डालने की जरूरत नहीं है। इस सोलर पम्पों की कीमत काफी ज्यादा है। अगर हम किसानों को सब्सिडाइज्ड करके देंगे, तो दूरदराज के अंदर जो किसान काम कर रहा है, ईमानदारी से अपने देश की सेवा करता है, उसके लिए मदद की जरूरत है, आज वह इनीशिअल स्टेज में होगा, अगर हम उसको सब्सिडाइज्ड करेंगे तो जो किसान आज बगैर पानी के खेती कर रहा है वह वन थर्ड यील्ड निकाल रहा है, नेशनल वेस्टेज भी हो रहा है और किसान की भी हालत नहीं सुधर पा रही है, इससे किसानों का फायदा होगा। वह जब आत्महत्या करता है तो हम उसको दो लाख रुपए दे देते हैं। इस तरह से हम उसकी दो लाख की मदद करने के लिए उसको आत्महत्या करने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं? अगर इस दो लाख रुपए में से एक लाख रुपया पहले दे देंगे तो उसके यहां पम्प लग जाएगा, जिससे उसका उत्पादन बढ़ जाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इस प्रकार उसे न तो आत्महत्या करनी पड़ेगी और न ही सरकार के ऊपर भी दोषारोपण होगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देते हैं तो सोलर एनर्जी की तरफ, पर्टिकुलरली रूरल एरिया के अंदर, सोलर पम्प के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए मार्किटिंग व्यवस्था अच्छी करने के लिए माननीय पवार साहब ने Commodity Exchange Market शुरू किया था। बहुत अच्छा ख्याल था। परन्तु क्या वाकई में किसान उसका उपयोग कर रहे हैं किसान तो उसका उपयोग करता भी नहीं है, उस बेचारे को पता भी नहीं है कि यह क्या है। इसका उपयोग अपने फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए जो लोग कर रहे हैं वे केवल स्पेकुलेशन के लिए कर रहे हैं। अगर इस पर हम रोक नहीं लगाएंगे तो हमारा जो इंफ्लेशन रेट बढ़ रहा है, इसके अंदर वह मददगार होता है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि पिछले साल Gawar Gum 2500 रुपए से 3000 रुपए प्रति क्विटल में उपलब्ध थी, इस साल इसका रेट एक लाख रुपए क्विटल तब बढ़ गया है। 2500 रुपए, 3000 रुपए क्विटल में मिलने वाली चीज एक लाख रुपए प्रति क्विटल तक कैसे बढ़ गई? इसके अंदर सट्टा हो रहा है, इसके अंदर स्पेकुलेटिव बिजनेस हो रहा है और कोई इसमें एक लिंक बनाकर

के अपना काम कर रहा है। इस ओर सरकार केवल देख रही है, कर कुछ भी नहीं रही है। उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं मागं करूंगा कि commodity exchange market बन्द कर देनी चाहिए। यह किसानों के किसी काम का नहीं है। इसका फायदा केवल कुछ व्यापारी ही उठा रहे हैं। इसमें कुछ ही फायदा उठाते हैं और हजारों खोते हैं। इस प्रकार उनको भी बचाया जा सकता है। अगर स्पेकुलेशन बन्द हो जाएगा तो हमारे इंफ्लेशन बढ़ने पर भी रोक लगेगीा अभी दो-तीन रोज पहले ही पेपर में आया था कि उनका नेक्स्ट टार्गेट अब सरसों की तरफ है। सरसों की भी वही हालत होगी जो Gawar Gum की हुई। क्या हम सिर्फ बैठे हुए ही ये चीजें देखते रहेंगे या उसके ऊपर एक्ट करेंगे? commodity exchange market को बन्द करने की जरूरत है। यह अपना जो परपज था, अपनी जो अपेक्षा थी और अपना ऑब्जेक्ट था वह प्राप्त करने के लिए मददगार साबित नहीं हुआ है, यह उल्टा जा रहा है।

इसे रोकने की जरूरत है, ऐसी मेरी मांग है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का खुलासा और करना चाहूंगा। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : ज्यादा समय नहीं मिलेगा। सिर्फ तीन मिनट में खत्म करिए, ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन : महोदय, अब मैं जो पॉइंट रेज करना चाहता हूं, खुद उस ट्रेड से जुड़ा हुआ हूं। मैं यह जाहिर करना चाहता हूं कि मैं ज्वैलरी ट्रेड से जुड़ा हुआ हूं। आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों ज्वैलर्स स्ट्राइक कर रहे हैं। उस के बारे में कल वित्त मंत्री महोदय ने कुछ कहा है, परन्तु उनकी मांग है कि सोने के आयात पर जो पहले कस्टम ड्यूटी तीन महीने पहले एक परसेंट थी, उसको दो परसेंट कर दिया गया है और बजट के समय उस को चार परसेंट किया गया। हमें उस पर एतराज नहीं है क्योंकि यह तो सभी जगह लगेगी।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : सिर्फ दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह ड्यूटी चार परसेंट लगे, उस पर कोई एतराज नहीं है, परंतु छोटे-बड़े सभी traders, सभी manufacturers का विरोध एक्साइज ड्यूटी को लेकर है और यह इसलिए है क्योंकि यह इंडस्ट्री नहीं है, यह कॉटेज इंडस्ट्री है। इस में लोग घर-घर में काम करते हैं। एक व्यक्ति प्रमुख होता है और उसके नीचे 50 लोग काम करते हैं। उन 50 में अलग-अलग काम करने वाले होते हैं-कोई कटाई का काम करने वाला होता है, कोई उड़ाई का काम करता है जिसे काला काम कहते हैं, कोई मीनाकारी करता है ...**(व्यवधान)**... कोई पॉलिश लगाने का काम करता है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कृपया समाप्त करें। जैन साहब, कृपया समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन : मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा। यह ड्यूटी उन व्यापारियों के लिए तकलीफदेह है और इसलिए उनकी मांग है कि इसके ऊपर से एक्साइज ड्यूटी हटायी जाए। मैं वित्त मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि वे उनकी मांग जायज होने के नाते मान्य करें। इसी प्रकार से उनकी दूसरी मांग दो लाख रुपए से ऊपर के बिल पर एक परसेंट लगाए गए "सेस" को हटाने के सम्बंध में है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इससे दो नम्बर का काम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा। आखिर हमें ब्लैक मनी बढ़ानी है या घटानी है? उसके लिए पहले 5 लाख रुपए का जो बंधन था, वह उचित है। अगर बिल 5 लाख के ऊपर होगा तो पैन कार्ड लगेगा, परंतु आजकल हो यह रहा है कि अगर 60 ग्राम की ज्वैलरी बनेगी तो उसका बिल भी 2 लाख रुपए हो जाएगा। आज साधारण आदमी भी इतनी ज्वैलरी ले लेता है। इस कारण इस के अंदर दिक्कतें आएंगी। इसलिए मेरी वित्त मंत्री जी से विनती है कि इस बंधन को पूरी तरह से हटाया जाए और उनकी इस मांग को मान्य किया जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सोना investment के तौर गिना जाता है। जब किसी गरीब को पैसे की जरूरत होती है, तब वह उसे बेचने आता है। उस आदमी के पास बैंक में किसी प्रकार का खाता नहीं होता है। वह अगर उसे चैक देगा, तो वह गरीब नहीं मानेगा।

[श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन]

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : उपसभाध्यक्ष महोदय, 20 हजार के ऊपर की purchase चैक से करना possible नहीं हो सकता। मैं मांग करूंगा कि उसकी लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर देना चाहिए। उसी प्रकार से ब्लैक मनी के ऊपर व्हाइट पेपर देने के बारे में वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है। हम उसकी राह देख रहे हैं। आप ने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष : धन्यवाद।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, when the hon. Finance Minister first came here, to this august House, way back in 1969 ...(*Interruptions*)... I still remember, I was in short pants, in kindergarten. Since then, he has presented seven Budgets. The only claim I have of the number 'seven' is that I have been here for just seven months. I am not an experienced Parliamentarian, nor, in fact, am I a trained economist, but, that having been said, what I will try to do over the next few minutes is to hold up a mirror to view the views of a housewife in Haldia, or a bank clerk in Hospet or a student in Bilaspur or a daily labourer in Bongaon. I have often heard this, not only here, but on television channels, which has caused us a lot of distress: when you give it to the poor, you call it 'subsidy', and when you give money to the corporates, you call it 'stimulus.'

Sir, a lot has been said on subsidy—Rs. 24,000 crores cut on fuel subsidy, Rs. 6000 crores cut on fertilizer subsidy; then, overall subsidy bill down from Rs. 2,13,000 crores to Rs. 1,13,000 crores. In fact, yesterday the hon. M.P., Mr. N.K. Singh, asked the Finance Minister, 'when he will bite the bullet', and he described four bullets being (a) LPG, (b) Diesel and Petrol, (c) Kerosene, and (d) Urea. My humble suggestion to the hon. Finance Minister is, please imagine that these are rubber bullets and please do not bite them; chew on them because we have lots of solutions to offer, alternative solutions. So, you chew on these bullets and please do not bite these bullets.

But the bigger point was raised by both sides actually. The hon. Leader of the Opposition mentioned it once, and it was also mentioned by the eloquent hon. M.P. speaking first from the Treasury Benches. From the Treasury Benches, they spoke of a concept, the concept of 'cooperative federalism'. It is indeed a very interesting concept. The Trinamool Congress would like to just provide you a different perspective today of 'cooperative federalism' without the letters 'co'. So, it would actually become not 'cooperative federalism' but 'operative federalism', and I would urge the hon. Finance Minister to look and judge his Budget, how he has done or how the Budget has done, based on this concept of 'operative federalism'.

Sir, there are a few other points. Let's take the first one, the CST and the GST issue. Now, yesterday, we heard the reply of the hon. Finance Minister in the Lok Sabha. You know what is happening on the CST, down from 4 to 3 to 2. The States, in

fact, are losing money, and a unilateral decision has been made not to give the States what is actually due to them. In case of West Bengal, it is Rs. 1200 crores. If you look at some of the other States, it is all between Rs. 800-1200 crores and Rs. 1500 crores. Now, this has been done unilaterally. In fact, yesterday, we heard that apparently, this was recommended by the Empowered Committee of Finance Ministers. But my question is, if everything, which the Empowered Committee of Finance Ministers recommends, is done, then, how come the Service Tax recommendation which was made by this Empowered Committee of Finance Ministers this year, was not listened to? So, the first question we need to ask ourselves is : is this 'operative federalism' denying the States of what really belongs to them by unilaterally taking these decisions? And, that is why we were not as gung-ho about GST because we feel there may be some devious intention.

Let us move on to a second point about, is this operative federalism? Let us look at the question of 'Bringing the Green Revolution to Eastern India', BGREI. Paddy production went up by 7 million tonnes—thanks to Rs. 400 crores, which was pumped in last year. What is the figure this year? Rs. 400 crores went up by 7 million tonnes, and if the hon. Finance Minister is really serious about bringing the Green Revolution to Eastern India—let me clarify that Eastern India is not Bengal, Bihar, Odisha, it also includes Eastern UP.—then that figure this year is paltry, Rs. 600 crores. In fact, if this is true operative federalism, then kindly look at the electricity consumption *per capita* of the country. These are very interesting statistics—Northern Region, 695 units; Western Region, 1116 units; Southern Region, 938 units—congratulations. But what about the East? I am talking about the electricity used not for airconditioners; it could be used for irrigation pumps. The East is 481 units. The North-East is even lower, i.e., 251 units. Is this 'operative federalism'? I ask the hon. Finance Minister to look at this Budget through the prism of 'operative federalism.'

On the third point, which I call, a-child-is-born point, every time a child is born in Bengal, there is no gift; rather a curse, Rs. 21,000, on that child's head—for every child born.

Bengal, Kerala and Punjab are known as debt-stressed States. A State is considered debt-stressed if the ratio of its consolidated debt and liabilities to total revenue receipts exceeds 300 per cent. In Bengal's case, it is 370 per cent; Punjab and Kerala would have their own numbers. Now, just imagine, this year, in the last fiscal, corporate debt—and I am talking about public sector banks restructuring corporate debt—of private companies was Rs.75,000 crores, up from Rs.5000 crores the year before the last. So, what are we talking about? We are talking about an interest and repayment moratorium in the form of an annual grant to Bengal and these other States for three years.

[SHRI DEREK O'BRIEN]

Let us move on to my next question about operative federalism, and this is about RIDF. Now, the Rural Infrastructure Development Fund, set up in 1995-96, was basically to support State Governments for priority sectors like agriculture, rural development and infrastructure development; 6.5 per cent was the rate of interest when money was lent to the States in 1995-96; and guess what that figure is now! It is not 7.5 or 8.5; it is now 9.5 per cent. So, a State Government, availing of an RIDF loan for critical areas like rural development, would find it very difficult, and I would really request the Finance Minister to bring that down from where it is now to 6.5 per cent.

Sir, I shall make two quick points more about operative federalism, and this does not concern only Bengal. The examples I use would be from Bengal. There are special grants for development of border areas. Now, there are, at least, eight such districts in Bengal which touch three different countries—Bangladesh, Nepal and...*(time-bell)* Sir, I would need a couple of more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : No, no. You have already taken three minutes more. There is no time. The reply has to be made at 4.00 p.m.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal) : Sir, yesterday, you had assured us that ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : No, no. Please, there is no time. The time allotted to the Congress and the BJP was cut short too.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal) : Also, there is the Backward Region Grant Fund where there are so many districts. Sir, from the point of view of operative federalism, I must ask: is this the North block trying to strategies to block the East block? Lots of Shakespearean quotes have been used in the last two-three days. May I also indulge in a quote? But this is not a Shakespearean quote: it is that of Qazi Nazrul Islam. And because of shortage of time and because the hon. Finance Minister is not here, I would read the lines in English. "Beat the drum, beat the drum! Who is that God, who is that King, who snatches away all our rightful things?" (*Time-bell rings*)

Sir, please allow me to make one point about something which is already there in the Budget document, this time, as a positive suggestion. There is the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme. This concept of reform, this concept of disinvestment, is a very abstract concept for the common man. There is a nice idea called the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme, which encourages investors investing Rs. 50,000 and below and they get some benefits. There is also the Government's plan for disinvestment of Rs. 30,000 crores in public sector companies. I would urge the hon. Finance Minister to merge and co-join these, so that the small investor can actually feel a part of this process of inclusiveness.

Sir, my last point is on gold. (*Time-bell rings*) Since 1 don't have much time, and I have three pages on gold, I would sum it up in a few words. For the artisans and everyone else, old is gold. So, don't tamper with the structure.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu) : Sir, this is not operative federalism but operation of federalism!

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now, Shri Ratanpuri. All hon. Members should cooperate, because we have to finish the discussion and reply has to be made at 4.00 p.m. So, everybody may kindly be brief.

SHRI G.N. RATANPURI (Jammu & Kashmir) : Sir, I understand that reconstruction and rehabilitation of militancy ravaged infrastructure in J&K, as also the holistic development of this State is declared a priority concern by the Central Government. This concern is emphasized quite frequently by the Central leadership and we have heard many special initiatives.

But I am sorry to say that the Budget does not reflect it. I am not able to find any allocations for Udhampur-Qazigund railway line not for proposed tunnel across Zojilla. The Government is committed to start work on this tunnel in the August next. There is no mention of Prime Minister's reconstruction plan under which the allocation has been reportedly cut down to Rs. 700 crore this year against last year's Rs.1200 crore. There is no indication that the Central Government intends to invest considerably towards the resolution of socio-economic problems of J&K.

Handicrafts sector constitutes the backbone of Kashmir economy. The shawl sector provides, direct and indirect, employment to half-a-million people, majority of whom are under-privileged. By withdrawing the Duty Entitlement Pass Book, this sector has been exposed to unfair competition from machine-made and machine-embroidered shawls and this will definitely add to the problems and woes of these marginalized people. I demand that Duty Entitlement Pass Book be restored or that the shawl sector be brought under Focus Benefit Scheme at par with carpet sector. Mass carpet weaving scheme and other activities of the Textiles Ministry merit more focus and funds and all the vacancies of this Ministry and its subordinate offices in J&K must be filled up.

Prime Minister's reconstruction plan should have been completed by now but, only 40 per cent of the funds have been utilized till November last. Every effort should be made to ensure completion of all the projects taken up under this Plan at the earliest. Adequate funds should be released to the executing agencies in time and, wherever necessary, time should also be extended.

The five working groups constituted by the Prime Minister, in the year 2004, to suggest ways and means to address socio-economic problems of Jammu & Kashmir

[SHRI G.N. RATANPURI]

have submitted their recommendations. This House was informed that "key recommendations of the working groups having impact on well-being of different sections of society have been implemented," but the State Government does not agree and is not aware of any recommendations having been implemented. This House has the right to know the real facts.

In pursuance to Dr. Rangarajan Committee's recommendations, the Prime Minister announced transfer of Dulhasti Power Project to J&K Government from NHPC, but NHPC has not shown any inclination to transfer any of its power houses to the State even against a mutually agreed upon and genuine compensation.

The rivers of Jammu & Kashmir have the potential to produce 20,000 MWs of power, but the State does not get even a few hundred megawatts. Under Indus Water Treaty, Government of India bartered away to Pakistan more than 99.5 per cent of J&K waters, leaving less than 0.5 per cent for the State. The J&K Government was not taken on the board while negotiating Indus Water Treaty.

In the year 2005, International Water Management Institute, in collaboration with Sir Rattan Tata Trust, Mumbai, conducted a study and calculated losses due to Indus Water Treaty at Rs.6500 crore annually. The study says, "The Treaty which was carried in the best interests of the nation has, however, deprived Jammu & Kashmir of using its own water resources and thereby severely affected the development of State. The Treaty has made Punjab prosperous by using the waters of eastern rivers for agriculture and power generation. This, however, put J&K behind by an estimated Rs.6500 crore annually. The losses are not there in the agriculture sector alone but, on a much higher scale in the generation of hydro power."

When the people of J&K compare this situation with the distribution of Ganga Teesta and Brahmaputra Rivers where the Central Government does not take even a step without the concurrence of the concerned State Government, they feel discriminated against, or may I say, cheated.

J&K has equally been wronged by the neighbouring State of Punjab. In 1979, a bilateral agreement was signed by the Chief Ministers of Punjab and J&K on the construction of Thein Dam, now rechristened as 'Ranjit Mahasagar Dam'. The dam was to be constructed by the Government of Punjab and it was bound to provide 15 per cent jobs and 20 per cent of electricity generated, and also 65 million cusecs of water to J&K. The 40 per cent of land occupied by the project belongs to Jammu & Kashmir.

The Government of Punjab has unilaterally cancelled this agreement and it has chosen to deny the full compensation for land to land owners. Ranjit Sagar Dam occupies only five to six per cent of Himachal Pradesh's land and still, this State is getting its

full share under the agreement, while the J&K Government has not been able to get any electricity or any jobs, and not even a drop of water, in the canal system that has been constructed at a cost of Rs.100 crores. Losses accrued to Jammu and Kashmir due to non-implementation of agreements on Thein Dam have been calculated at Rs.8,650 crores. The Central Government has shown no intention of compensating these or the losses accrued to J&K due to Indus Water Treaty. State's liabilities have equalled more than 66 per cent of the GSDP and the debt services are almost equivalent to the Annual Plan. The situation demands immediate concrete steps, so that the targets of fiscal discipline fixed by the 13th Finance Commission can be realised by Jammu and Kashmir Government too.

The people of Jammu and Kashmir, particularly the young generation, want to know that if the resolution of the political issues has to wait for a national consensus, what stops the Central Government from undoing the wrongs of Indus Water Treaty, renegotiating it or compensating the State for losses accrued. Jammu and Kashmir has also demanded that the State should be relieved of the debt burden that has accrued due to delayed implementation of Central assistance formula in 90:10 ratio for special category States.

Last year, the Finance Minister announced special packages of Rs.100 crore and Rs. 150 crore for Ladakh and Jammu regions respectively. Having borne the brunt of terror and mayhem for more than two decades, the people of the Valley had felt let down. They could not suspect that they were in for a bigger shock. The Central Government did not provide any funds for this special package but forced the State to shelve out Rs. 250 crore from its Annual Plan.

Jammu and Kashmir, due to multiple reasons, is far behind most of the States in allocation and then, also in utilisation of Central assistance. Centrally-sponsored schemes and Central Government projects are also running behind schedule at a snail's pace. The reasons put forward for this sorry state of affairs are more often unconvincing.

The people quote the example of Uri Power Project that was constructed in a record time in the most difficult terrain, during the worst phase of militancy and in spite of the abductions of engineers. They have full faith in the might and resourcefulness of the Central Government; only the intentions remain blurred.

The Government of India has also to finance generously the projects related to tourism, infrastructure development and world-class tour, travel and accommodation facilities at all the tourist destinations in Jammu and Kashmir.

Roads constitute the major indicator of growth and development anywhere. But, in the absence of railways, road network is the only lifeline of Jammu and Kashmir and still, we do not match the road network of those States that are gifted with vast

[SHRI G.N. RATANPURI]

railway network. Less than half of our total road length of 26,711 kilometres is blacktopped.

Our allocations under the CRF, PMGSY, Bharat Nirman and NABARD are not adequate and their utilization is even lesser. Since 2000-01, only 46 out of 95 projects were completed and only Rs. 49,784 lakh, out of an allocation of Rs. 82,127 lakh, were expended under CRF. Similarly, only half or even lesser allocations have been expended under PMGSY, Bharat Nirman and NABARD also.

Sir, people crave for quick, result-oriented measures. Announcements of big packages have lost credibility due to sluggish implementation and are taken just as rhetoric. Thank you. Sir.

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे वित्त मंत्री आदरणीय प्रणब मुखर्जी देश के जाने-माने उन नेताओं में से हैं जो देश के विकास के प्रति संवेदना रखते हैं। लेकिन वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसके बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में जो allocation हुआ है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह यूपीए सरकार की विफलता की झांकी है। देश में फैले भ्रष्टाचार और महंगाई के कारण वित्त मंत्री जी के सामने जो मर्यादा थी, उसका भी इसमें दर्शन हो रहा है।

वित्त मंत्री जी ने आयकर दाताओं को 1,80,000 से 2,00,000 तक 20,000 रुपए की कर में राहत की है। इससे करदाता के करीब दो हजार रुपए बचेंगे। वित्त मंत्री जी ने आम लोगों के ऊपर जो सर्विस टैक्स बढ़ाया है, वह दो प्रतिशत बढ़ाया है। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी ने एक हाथ से जो कुछ दिया, दूसरे हाथ से सब कुछ वापस ले लिया, मानो जोर का झटका धीरे से लगा। अब सभी को पता चल रहा है कि इससे कोई लाभ नहीं, बल्कि नुकसान ही है।

मेरी वित्त मंत्री जी से विनती है कि जिस तरह आम आदमी महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, उसको राहत पहुंचाने के लिए वे और relaxation दें। हमारे LoP जेटली जी ने बजट पर discussion में सही बात कही थी कि आम आदमी, करदाता जो कमाता है, सरकार उसका 60 per cent प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वापस ले लेती है। मुझे लगता है कि इससे देश के लोगों में निराशा पैदा होगी और आने वाले समय में देश के विकास के ऊपर भी उसका नकारात्मक असर दिखने लगेगा।

महोदय, यह देश कृषि प्रधान देश है। यहां करीब 60 से 65 प्रतिशत लोग डॉयरेक्ट या इन-डॉयरेक्ट खेती से जुड़े हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी जी लोगों के बीच जाते थे तब वे एक बात कहते थे कि इस देश की आत्मा गांव में है। इस देश की आत्मा की धड़कन खेतों और खलिहानों में सुनाई देती है। गांधी जी का यह विश्वास था कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर करना है तो पहले गांव को आत्मनिर्भर करना होगा, गांवों का विकास करना होगा। अभी देश के जो हालात हैं, मुझे लगता है कि इसमें कई सुधारों की जरूरत है। मैं किसान के नाते वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि कृषि के सेक्टर में जो बजट एलोकेट किया है, उसमें 18 प्रतिशत तो बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए अच्छी बात कही थी कि हमने इस साल कृषि में 18 प्रतिशत वृद्धि की है। महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। कृषि का बजट 20,800 करोड़ तो बढ़ा है, लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की कुल GDP में कृषि का योगदान 14.5 प्रतिशत है। इस देश के बजट का कद 14,90,925 करोड़ है। इस साल कृषि का बजट 20,800 करोड़ है। अगर पूरे बजट का प्रतिशत निकाले तो यह 1.5 से 2 तक होता है। जिस कृषि का GDP में रेश्यो करीब 13.9 प्रतिशत हो, तो मुझे लगता है कि कृषि का उत्पादन कृषि की आय देश के GDP में जितनी है, इतना बजट कृषि को एलॉट करेंगे, तभी हम आने

वाले समय में जो हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट करीब-करीब 3 प्रतिशत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर सकेंगे।

महोदय, मैं गुजरात का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं यहां गुजरात की मार्किटिंग करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। गुजरात ने पिछले दस सालों में कृषि के क्षेत्र में जो अद्‌भुत क्रांति की है, यह कैसे संभव हुई, मैं इसका जिक्र भी करना चाहता हूं। गुजरात में सन् 2001 से लेकर 2011 तक 9,000 करोड़ की आय थी। आज गुजरात की 2011 की आय करीब-करीब 89,000 करोड़ तक पहुंच गई है।

इसके पीछे सरकार की तपस्या है, political will है और commitment भी है। गुजरात में कृषि यात्रा निकाली गई। अभी हमारे ईश्वरलाल जी ने, हमारे एन.सी.पी. के सहयोगी ने बताया कि drip irrigation के लिए और बजट की जरूरत है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको आनन्द के साथ कहना चाहता हूं कि गुजरात ने एक कंपनी बनाकर किसानों के लिए drip irrigation का 15 सौ करोड़ रुपये का बजट रखा है। पूरे गुजरात में किसान drip irrigation अपना रहा है। इससे पानी की बचत होती है और पानी का कंजप्शन भी कम होता है और गुजरात में कृषि में जो उत्पादन बढ़ा है, इसका मुख्य कारण भी drip irrigation है। गुजरात ने सोइल टेस्टिंग में भी बहुत काम किया है। इसके पीछे स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना बजट लगाया है। मेरी विनती है कि केंद्र सरकार भी इस बजट में कृषि के लिए और प्रावधान रखे। इस बजट को करीब-करीब पांच गुना बढ़ाने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष जी, यह अच्छी बात है कि वित्त मंत्री जी ने 2012-12 के लिए कृषि ऋण पर 1 लाख करोड़ रुपये से राशि बढ़ाकर 5 लाख, 15 हजार करोड़ रुपये कर दी है। यह भी अच्छी बात है कि समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट भी दी गई है, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट यह भी बता रही है कि देश में आधे किसानों को ऋण नहीं मिलता है, इसलिए हमें इसकी भी व्यवस्था करनी होगी कि किसानों को बैंक द्वारा समय पर ऋण मिले।

उपसभाध्यक्ष जी, शिक्षा का क्षेत्र जो है, उसकी ओर भी देखना होगा। ऐसा कहा जाता है कि कंकर में से संकर पैदा करने की ताकत जिस क्षेत्र में है, वह शिक्षा का क्षेत्र है। पूरे विश्व में, शिक्षा के क्षेत्र में 35 प्रतिशत निरक्षरता हमारे भारत में है। जो बजट का एलॉटमेंट है, वह केवल 0.73 प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र को दिया गया है, इसलिए इसमें भी और बढ़ावे की जरूरत है। हमारे युवा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व में **(समय की घंटी)** मैं अभी कंक्लूड करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : टाइम नहीं है, खत्म कीजिए।

श्री भरतसिंह प्रभात सिंह परमार : उपसभाध्यक्ष जी, मैंने पाँच बार तैयारी की है और मुझे आज बोलने का मौका मिला है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : परमार जी, सुनिए, ...**(व्यवधान)**... मैं क्या करूँ, आपकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया है। मैं क्या करूँ, अभी एक और स्पीकर हैं।

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार : उपसभाध्यक्ष जी, ...**(व्यवधान)**... यह ऑफीशियल मेडेन स्पीच है ...**(व्यवधान)**... मैंने आपसे विनती की और आपने बोलने दिया, यह मेरी ऑफीशियल मेडेन स्पीच है ...**(व्यवधान)**... पाँच मिनट और दीजिए ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : नहीं, क्योंकि अभी एक स्पीकर और है ...**(व्यवधान)**... You have left only one minute.

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार : उपसभाध्यक्ष जी, ...**(व्यवधान)**... मैं जल संकट की बात करता हूं कि आने वाले समय में ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : एक और स्पीकर हैं, There is one more speaker from your party.

श्री भरतसिंह प्रभातसिंत परमार : उपसभाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में कन्क्लूड करता हूं कि आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप उधर देखिए, एक भी मिनट बाकी नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार : उपसभाध्यक्ष जी, तीसरा विश्व युद्ध जल संकट के ऊपर लड़ा जाएगा। ऐसा बता रहे हैं कि जल की के आधार पर तीसरा विश्व युद्ध होगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : ओ.के. बैठिए ...**(व्यवधान)**... There is no time left for the other speaker from your party.

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार : हमें आपके माध्यम से यह कहना है कि जब पूरा देश सूखे की चपेट में है, तब हम आने वाले समय में वाटर मैनेजमेंट ठीक तरह से करें तो अच्छा होगा। मैं इसके साथ ही अपनी स्पीच समाप्त करता हूं, अस्तु।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : ठीक से करेंगे, आप बैठिए, जो जाएगा। धन्यवाद परमार जी।

श्री शादी लाल बत्रा (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, धन्यवाद। आदरणीय प्रधान मंत्री जी की देख-रेख में माननीय वित्त मंत्री जी ने, जो अनुभवी नेता भी हैं, भारत के मुश्किल में जा रहे जिन हालातों में बजट पेश किया, मैं स्वयं को उससे जोड़ता हूं। यदि आप बजट की ओर देखें तो 2009-10 और 2010-11 में विकास दर 8.4 प्रतिशत थी, लेकिन यह 2011-12 में लुढ़ककर 6 पर आ गई। वित्त मंत्री जी को बजट पेश करना था, इसलिए उन्होंने हर चीज और सभी हालातों को देखकर कि देश का विकास कैसे हो, देश आगे कैसे बढ़े, जो बजट पेश किया है मैं उसकी सराहना करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, भारतवर्ष की आबादी 120 करोड़ से ऊपर जा रही है और 60 परसेंट से ज्यादा लोग गाँवों में रहते हैं। जो लोग गाँवों में रहते हैं, वे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पर निर्भर हैं। कृषि मानसून पर निर्भर है और मानसून का एक gamble है। अगर मानसून आ जाए, तो कृषि हो जाएगी, अगर मानसून ज्यादा आएगी, तो flood आ जाएगा, अगर मानूसन कम आएगी, तो कहर पड़ जाएगा और सारा असर उस किसान पर पड़ेगा, जो अपनी आँखें लगा कर बैठा था कि मेरी फसल होगी, मेरे घर का गुजारा होगा और मैं आगे चलूँगा। बारिश नहीं हुई, कहर पड़ गया, तो उसके पास और कोई चारा नहीं, सिवाय इसके कि वह एक साल और इंतजार करे और इंजतार करने के बाद फिर जब फसल आएगी, तो वह घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च वगैरह वहन करेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, हमें देखना होगा कि जब देश आजाद हुआ था और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, "जय जवान जय किसान" और और फिर एक green revolution आया था। आबादी कितनी बढ़ गई थी, लेकिन उस आबादी का पेट भरने के लिए हिन्दुस्तान में इतना अनाज पैदा हो गया था कि ह सब कहते थे कि हम आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन आज ऐसा नहीं होने का कारण क्या है? इसमें एक चीज है। मैं वित्त मंत्री जी और सदन को एक सुझाव देना चाहूँगा कि अगर हमें खेती को बढ़ावा देना है, खेती का विकास करना है, तो सबसे पहले तो उत्तम बीज हों manure हो, खाद हो और उसके बाद जो पानी की समस्या आ रही है, वह भी दूर हो। पानी की समस्या किस प्रकार हल होगी? मेरे दो भाइयों ने यह कहा कि drip irrigation हो या sprinkler हो। इसे पानी का बचाव भी होता है और पानी सीधा खेत को जाता है। ये उस पेड़ के पास जाएगा, जिसे पानी की आवश्यकता है। अगर हम इसको पूरी तरह से control करके ऐसा करें, तो खेती बढ़ सकती है। खेती बढ़ेगी, खेतों में पैदावार होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस फसल के रखरखाव के लिए हमें गोडाउन चाहिए। जब हमें उस फसल के रखरखाव के

लिए गोडाउन मिलेगा, तब हिन्दुस्तान के हर नागरिक के मुँह में वह अन्न ले जाने की हमारी कोशिश पूर्ण होगी, लेकिन होता यह आ रहा है कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं, इतने गोडाउंस नहीं हैं कि जो पैदावार हो, हम उसका रखरखाव कर सकें और आखिर तक जब तक उसकी खपत न हो जाए, उसका बचाव होता रहे। इसके क्या कारण होते हैं? मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को एक सुझाव दूँगा कि उन्होंने प्रावधान किया है कि और गोडाउंस बनाए जाएँ, 5 लाख टन के बनाए जाएँ, 10 लाख टन के बनाए जाएँ, लेकिन हमारी फसल कितनी होगी और कितनी आसमान के नीचे होगी और किस प्रकार रखी जाएगी, इसका प्रावधान करना होगा। उन गोडाउंस के लिए प्रावधान करना बहुत जरूरी है। इसलिए उनके लिए प्रावधान किया जाए। जब अनाज गोडाउन में रखा जाएगा और वह आसमान के नीचे रह कर धूप से, बारिश से खत्म नहीं होगा, तो हमारे सारे नागरिकों को और खास कर गरीबों को इसका जो फल मिलेगा, वह फल बहुत ही अच्छा होगा और इसके लिए हम कहेंगे कि हमारा विकास हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष जी, बात यहाँ खत्म नहीं होगी। बात आगे चलती है कि जो पैदावार हो रही है, उनको मिली और हमने रख ली, लेकिन एक बात और होती है कि आज महँगाई बढ़ती है। महँगाई के कारण क्या हैं? महँगाई के पीछे आपने देखा होगा कि सब्जियों और फल की जो पैदावार हुई, वह कम हुई। फलों की पैदावार कम हुई, यह कम हुई या कम बनाई गई, यह एक बात थी, लेकिन दूसरी बात यह थी कि यह एक प्रदेश में पैदा हुई और दूसरे प्रदेश में उसके जाने के लिए सुविधाएँ चाहिए थीं, वे सुविधाएँ नहीं मिलीं। इसके पीछे भी एक बात है। अगर हम चाहते हैं कि विकास हो, सब्जियाँ पैदा हों, तो क्यों न अगर हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि सब्जियों की collection के लिए refrigerated vans हों। Refrigerated vans मंडी में आकार cool chain के जरिए उसका प्रसार करें। cool chain क्या है जब refrigerated van में सब्जियाँ आएँगी, तो पहले उनकी washing होगी, फिर grading होगी, उसके बाद packing करने के बाद हम उन्हें दूसरे प्रदेशों को भेज सकेंगे। अभी cool chain का प्रचलन बहुत कम है। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि आपने इसका प्रावधान किया कि cool chain बने, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसा नहीं कर रहे हैं और कुछ प्रदेश ऐसा कर रहे हैं। जो प्रदेश ऐसा कर रहे हैं, अगर हमने उन्हें प्रोत्साहित करके उनकी सब्सिडी, उनका stimulus fund ज्यादा बढ़ा दिया, तो वे प्रदेश, जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वे भी ऐसा करेंगे। इसके लिए आवश्यकता है कि हम आगे चलें और सब्जियों और फलों के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि देश में उनकी जितनी जरूरत है, वह पूरी हो सके।

उपसभाध्यक्ष जी, वैसे तो परमात्मा की तरफ से दो ही जातियां होती हैं, एक अमीर की और एक गरीब की, लेकिन हम इन्सानों ने उनको बहुत सी डिफरेंट केटेगरीज में बांट दिया। इसके बाद उसमें कई कमिशन भी मुकर्रर करने के बाद हरेक आदमी अपना-अपना रिज़र्वेशन क्लेम करने लगा। अगर अमीर और गरीब की तरफ देखें, तो हमें गरीब को ऊपर लाने के लिए काम करना होगा। अगर कोई टैक्स लगता है, अमीर तो टैक्स दे देगा लेकिन गरीब कहां से देगा, यह बात सोचनी होगी।

आप देखें, गांवों में जो 60 प्रतिशत आबादी रहती है, वह गरीबी रेखा से नीचे रहती है, उनके के लिए क्या हो रहा है? उनके लिए न तो पूरा काम हो रहा है, न ही उन्हें पूरी शिक्षा मिल रही है, न ही उनको स्वास्थ्य का पूरा लाभ मिल रहा है और न ही उनको पक्की सड़कें मिल रही हैं। मैं वित्त मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि भारतवर्ष का पूरा विकास हो और वह विश्व का नम्बर एक देश बन सके, उसके लिए आपको उन गांव वालों की तरफ देखना होगा, जो हर सुविधा से महरूम हैं।

शिक्षा सबसे प्राइमरी होती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है, जो इन्सान को अपने पांव पर खड़ा करने क लिए, आगे बढ़ने के लिए साधन देती है। अगर गांव में शिक्षा नहीं होगी, तो एक तो यह होगा कि उनके पास खेती के लिए नयी सोच नहीं होगी, वे साइंटिफिक इंस्ट्रुमेंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, वे अच्छे बीज नहीं ले सकेंगे और हर प्रकार से वे पिछड़ते जाएंगे। आज वही हो रहा है। अगर आज हम देखें तो बीपीएल की संख्या बढ़ रही है। बीपीएल की संख्या बढ़ने के पीछे कारण क्या है? कारण एक ही है कि जो उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए थी, वह सुविधा नहीं मिल रही है।

[श्री शादी लाल बत्रा]

3.00 P.M.

आज एक ऐसा मौका आया है कि मैं अपने आदरणीय वित्त मंत्री जी से कहूं कि वित्त मंत्री जी, आप गांवों के उन गरीबों की तरफ देखिए, जिन गरीबों के पास साधन नहीं हैं। उनके विकास के लिए आपने जो प्रावधान किए हैं, उन प्रावधानों को और अधिक बढ़ाइए। उनको अच्छे बीज मिलें, उनको अच्छी खाद मिले।

किसानों को बीज देने के लिए दो कंपनियां बनी थीं। 1963 में National Seed Corporation बनी और उसके बाद 1969 में बनी और उसके बाद 1969 में State Farm Corporation of India बनी थी। 1963 से लेकर आज दिन तक National Seed Corporation क्या कर रही है? वह सिर्फ 5 प्रतिशत किसानों की जरूरतों को पूरा कर रही है। यदि वह केवल 5 परसेंट किसानों की जरूरतों को ही पूरा करती है तो बाकी के 95 प्रतिशत किसान कहां जाएंगे और कहां से बीज लाएंगे? वे लोग उन unscrupulous कंपनियों के पास जाएंगे, जिनके पास कोई मर्यादा नहीं है, कोई सोच नहीं कि हमें अपने देश के साथ क्या करना चाहिए। ऐसी कंपनियां किसान को बीज तो बहुत दे देती हैं, लेकिन जब वह बीज किसान के पास जाता है, तो उसकी फसल नहीं होती और वह खत्म हो जाता है। इसके लिए हमें सोचना होगा। Seed Corporation of India की जो केपेसिटी है, सबसे पहले हमें उसको बढ़ाना होगा और उसके बाद यह देखना होगा कि किसाना जो भी बीज लेकर जाए, उस बीज के ऊपर मुहर लगी हो, वह सर्टिफाइड हो। अगर उसका कोई नुकसान होता है, तो वह कम्पनी, जहां से वह बीज गया था, वही उसके नुकसान की भरपाई करे या फिर सरकार करे, आपको इसका प्रावधान करना होगा।

एक बात और आती है, आज एमएसपी तय किया जाता है, लेकिन एमएसपी किस प्रकार तय किया जाता है? आपने खेती को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया नहीं, कोई बात नहीं, संविधान में नहीं है इसलिए खेती को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला, लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं। हम यह देखें कि एमएसपी मुकर्रर करने के लिए कैसे उचित प्रावधान हों। इसके लिए मेरा एक सुझाव है। अगर हमने एमएसपी मुकर्रर करना है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है, प्लस 50 प्रतिशत और जमा करके एमएसपी मुकर्रर किया जाए। कॉस्ट प्राइस, प्लस 50 प्रतिशत। इससे होगा यह कि आज जमीनों की जो कीमत है, किसान को उसका उचित रिटर्न मिलेगा और किसान को रोटी खाने के लिए एक काम मिलेगा। यदि ठीक एमएसपी मुकर्रर हो गई फिर उसको जो पैदावार मिलेगी, इससे उसके पास साधन हो जाएंगे। ऐसे में उसके पास जो दूसरे काम हैं, वह उनके लिए भी सोचेगा।

आज भ्रूण हत्या की बात हो रही थी। भ्रूण हत्या क्यों हो रही है? मैं बताना चाहता हूं कि इसकी संख्या गाँवों में ज्यादा है, लेकिन इसके पीछे उनकी कुछ न कुछ मजबूरी भी है। मैं यह नहीं कहता कि स्त्री की दुश्मन स्त्री है, क्योंकि गर्भपात करवाने वाली भी स्त्री होती है और पैदा होने वाली बेटी भी स्त्री होती है। इसके पीछे उसके कुछ मजबूरी होती है और वह मजबूरी ही उससे ऐसा काम करवाती है। इसलिए भ्रूण हत्या न हो, उस मजबूरी ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude. 4.00 p.m. पर रिप्लाई होना है।

SHRI SHADI LAL BATRA : Sir, I am a disciplined soldier. आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : 4.00 p.m. पर रिप्लाई होना है।

श्री शादी लाल बत्रा : भ्रूण हत्याएं न हों, ये सारी चीज़ें गरीबी के साथ जुड़ी होती हैं और गरीबी को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि उनका विकास हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश) : सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। पिछले साल ही तरह इस साल भी एक बजट आया और कहा गया कि सब ठीक है। मैं सिर्फ यह शेर पढ़ कर सुना दूँ कि:

तुमको काली घटा को भी पहचानना नहीं आता,
नशेमन में से धुआँ उठता है, तुम कहते हो सावन है,
हकीकत तो यह है कि एक-एक बन्दा
यहाँ परेशान है गरानी के थपेड़ों से।

कहते हैं, कि फिक्र न करो, सावन आने वाला है। कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जिन लोगों ने यह देश आज़ाद किया था, उनकी निगाहें यह आरजू लेकर अपने रब से जाकर मिल लेंगी। मेरे जैसे लोग यह इंतजार करते रहे कि सब ठीक हो जाएगा। आज हम उस मंजिल पर खड़े हैं, जहाँ यह नहीं मालूम कि किस गली में शाम हो जाएगी, लेकिन कहा यह जारहा है कि सब ठीक हो रहा है। हक़ीकत यह है कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो नाइन प्वाइंट समथिंग थी, आज वह छ: पहुंच गयी। कहने लगे, सब ठीक है। यह क्यों है, ये नहीं बताते। Mismanagement of corruption की वजह से हम यहाँ खड़े हो गए हैं। यह हमारी बुनियाद है। हम दो कदम आगे चलते हैं और चार कदम पीछे चलते हैं। यह बजट को लाने से पहले यह नहीं सोचा गया कि अगला जो 12th Plan आ रहा है, जिसमें हमंडे 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, वह हम कहाँ से लाएँगे? इसकी कोई प्लानिंग हमारे पास नहीं है। आपको एक alternative ढूँढ़ना पड़ेगा और आपके पास एक alternative है। Standards & Poor's की रिपोर्ट में लिखा है, Islamic finance banking can play a role in funding Asia's infrastructure. हमारे पास एक सॉल्यूशन इस्लामिक बैंकिंग का है। बैंकों के नेशनलाइजेशन के साठ साल हो गये, लेकिन 40 परसेंट से ज्यादा लोग अभी तक बैंकिंग तक नहीं पहुँच सके हैं। गरीबी का आलम यह है कि गरीबी की रेखा न जाने कितनी सतह नीचे चली गयी है और रइसों का आलम यह है कि prosperity के न जाने कितने islands बन गये। इसको दूर करने के लिए प्लानिंग कमीशन के डा. रघुराम राजन ने एक रिपोर्ट में कहा, प्लानिंग कमीशन से रिक्वेस्ट की, इनसे कहा कि आप इस्लामिक बैंकिंग को इस मुल्क में लाइये। केरल में 40 हजार करोड़ रुपये unaccounted money है। क्योंकि, हमारी कौम में इंटरेस्ट मना है, इसलिए बहुत से लोग बैंकों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सिर्फ केरल में एक अकाउंट में 40 हजार करोड़ रुपये पड़े हैं, जो 10 परसेंट की दर से हर साल बढ़ते हैं। ऐसी रकम पूरे हिन्दुस्तान में कितनी है, इसका तसव्वुर फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, उसको वह इंफ्राट्रक्चर में नहीं जोड़ रहा है। मुसलमान तो वह पैसा लेना नहीं चाहता, लेकिन अगर सरकार उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, तो देश का कितना भला होगा? लेकिन, पता नहीं क्या वजह है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि यू.के., फ्रांस, जापान, चाइना, यू.एस.एस.आर. के सारे मुल्क, सिंगापुर और मलेशिया ने इसको accept कर लिया है। अगर आप इस्लामिक बैंकिंग से घबराते हैं, तो इसे आप alternative banking system बना कर कर दीजिए। इससे आपको इतना फंड मिलेगा कि आप अपने 12th Plan में काफी पैसा लगा सकेंगे, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हमारे बहुत से experts, जिनमें हमारे ऑनरेबल प्रोफेसर स्वामीनाथन जी भी थे, जो कि यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने भी और लोगों के साथ यह recommend किया कि फंड लाने का यह भी एक alternative हो सकता है, लेकिन मुश्किल यह है कि उस तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे ही इस्लामिक नाम आता है, तो एकदम खौफ आता है कि कहीं यह आतंकवादियों का पैसा तो नहीं आएगा? आप उसे अपने बैंक में रखिए और उसका एक नाम रख दीजिए, आप उसको alternative banking कर दीजिए, उसको बैंक से जोड़ दीजिए। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एक विंडो खोल दीजिए। आप बंगलादेश, यू.के. आदि जब जगह देखें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है।

मुसलमान का जो इंटरेस्ट का पैसा है, वह एक दूसरे बैंकिंग के थ्रू जा रहा है। मुसलमान एंटरप्राइज नहीं है, उसका पैसा 80 परसेंट नॉन-मुस्लिम यूज करते हैं। अदरवाइज वह हिन्दुस्तान के एक पूरे खाके में पूरे इंफ्रासट्रक्चर में इस्तेमाल हो सकता है। उसकी तरफ रिजर्व बैंक या फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई तवज्जुह नहीं कर रही है। मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त हमको वह पैसा डेवलप करना है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि इनकी रिपोर्ट कहती है कि

[श्री मोहम्मद अदीब]

1.5 ट्रिलियन डॉलर चाहिए अगले पांच साल के मंसूबों में। एक आल्टरनेटिव आपके पास है। मैं उसके लिए बराबर फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुज़ारिश करूंगा कि अगर आप आल्टरनेटिव बैंकिंग नहीं खोल सकते हैं तो कम से कम एक तरीका यह कीजिए कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और या किसी भी नेशनलाइज़्ड बैंक में एक विण्डो खोल दीजिए, क्योंकि इस इलाके से मुसलमानों का वह पैसा जो इंटरेस्ट के नाम से बैंकों में पड़ा हुआ है, वह यूटिलाइज़ हो जाएगा और इससे मुल्क का भला हो जाएगा। आप इसको मॉनिटर कीजिए और एक कमेटी बनाइए, जिस तरह से रघुराजन साहब ने कहा और दूसरे लोगों ने कहा, मेरे पास पूरी लिस्ट है हिन्दुस्तान और दुनिया भर के लोगों की, जिन्होंने इसको कहा है कि यही एक आल्टरनेटिव बनता है और इसका यूरोप फायदा उठा रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। इसलिए कि अमेरिका का जो सिस्टम है उसको नुकसान होगा, जो मिडल ईस्ट में हमारे हिन्दुस्तानी रहते हैं और जो दुनिया भर में हमारे हिन्दुस्तानी रहते हैं, उनका पैसा भी हिन्दुस्तान में उस तरीके से उस बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा, जिससे हमको अगले बजट या अगले पांच साला मंसूबों में फायदा होगा। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को इस पर तवज्जह देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस पर ज़रूर कोई न कोई ज़िम्मेदारी से जवाब देंगे, क्योंकि विण्डो खोलने के बाद फिर आप एक कमेटी बना दीजिए और उसको देखिए कि अगर उसको कुछ तरमीम करना है तो उसको देखिए, मॉनिटर करिए कि पैसे कहां से आ रहे हैं। हमारे बैंकों में लोग पैसे नहीं डाल रहे हैं। आप जाकर देखिए कि यह पैसा घरों में पड़ा हुआ है, ब्लैकमनी की शक्ल में पड़ा हुआ है। यह सब का सब पैसा व्हाइट हो जाएगा और जब व्हाइट होगा तो इससे देश का कितना भला होगा और कितनी इसकी ज़रूरत पड़ेगी।

इसके अलावा इस बजट के सिलसिले में मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। एक, यह कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो सिफारिशें की थीं। एक, यह कहा था कि कारपोरेट टैक्स रिलीजियस प्लेसेज का आप खत्म कर दें, उसका कोई ज़िक्र इसमें नहीं है। दूसरी उनकी सिफारिश यह थी कि RTE को सेपरेट करें माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन से। उसकी भी कोई सिफारिश नहीं है। तीसरी बात, जो मैं उत्तर प्रदेश के मुताल्लिक कहना चाहता कि उत्तर प्रदेश आज बहुत पिछड़ गया है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वहां बिजली और सड़कों पर पैसा लगाने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी तादाद में आलू का प्रोडक्शन होता है। इस बजट में मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि देहातों में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए पर्याप्त पैसे का इंतज़ाम करें और अगर उत्तर प्रदेश खड़ा होगा तो यह देश भी खड़ा हो जाएगा। इन अल्फाज़ के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

†[**جناب محمد ادیب (اتر پردیش)** : سر، بہت بہت شکریہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک بجٹ آیا اور کہا گیا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں صرف یہ شعر پڑھ کر سنا دوں گا کہ:

تم کو کالی گھٹا کو بھی پہچاننا نہیں آتا
نشیمن میں سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے
حقیقت تو یہ ہے کہ ایک – ایک بندہ
یہاں پریشان ہے گرانی کے تھپیڑوں سے۔

کہتے ہیں، فکر نہ کرو، ساون آنے والا ہے۔ کہتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے یہ دیش آزاد کیا تھا، ان کی نگاہیں یہ آرزو لے کر اپنے رب سے جاکر مل لیں گی۔ میرے جیسے لوگ یہ انتظار کرتے رہے

† [Transliteration in Urdu scrip]

کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج ہم اس منزل پر کھڑے ہیں، جہاں یہ نہیں معلوم کہ کس گلی میں شام ہو جائے گی، لیکن کہا یہ جارہا ہے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جی۔ڈی۔پی۔ کی گروتھ جو نائن پوائنٹ کچھ تھی، آج وہ چھ پر پہنچ گئی۔ کہنے لگے، سب ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نہیں بتاتے۔ Mismanagement of corruption کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری بنیاد ہے۔ ہم دو قدم آگے چلتے ہیں اور چار قدم پیچھے چلتے ہیں۔ اس بجٹ کو لانے سے پہلے یہ نہیں سوچا گیا کہ اگلا جو بارھواں پلان آ رہا ہے، جس میں ہمیں 1.5 ٹریلین ڈالرس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم کہاں لائیں گے؟ اس کی کوئی پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کو ایک alternative ڈھونڈنا پڑے گا اور آپ کے پاس ایک alternative ہے۔ Standards & Poor's رپورٹ میں لکھا ہے، Islamic finance banking can play a role in funding Asia's infrastructure. ہمارے پاس ایک سالیوشن اسلامک بینکنگ کا ہے۔ بینکوں کے نیشنلائزیشن کے ساٹھ سال ہو گئے، لیکن 40 فیصد سے زیادہ

لوگ ابھی تک بینکنگ تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ غریبی کا عالم یہ ہے کہ غریبی کی ریکھا نہ جانے کتنی سطح نیچے چلی گئی ہے اور رئیسوں کا عالم یہ ہے کہ prosperity کے نہ جانے کتنے islands بن گئے۔ اس کو دور کرنے کے لئے پلاننگ کمیشن کے ڈاکٹر رگھورام راجن نے ایک رپورٹ میں کہا، پلاننگ کمیشن سے ریکویسٹ کی، ان سے کہا کہ آپ اسلامک بینکنگ کو اس ملک میں لائیے۔ کیرل میں 40 ہزار کروڑ روپے unaccounted money ہے۔ کیوں کہ ہماری قوم میں انٹرسٹ منع ہے، اس لئے بہت سے لوگ بینکوں سے انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں۔ صرف کیرل میں ایک اکاؤنٹ میں 40 ہزار کروڑ روپے پڑے ہیں، جو 10 فیصد کی در سے ہر سال بڑھتے ہیں۔ ایسی رقم پورے ہندوستان میں کتنی ہے، اس کا تصور فائنینس ڈیپارٹمنٹ نہیں کر رہا ہے، اس کو یہ انفراسٹرکچر میں نہیں جوڑ رہا ہے۔ مسلمان تو وہ پیسہ لینا نہیں چاہتا، لیکن اگر سرکار اس پیسے سے

[श्री मोहम्मद अदीब]

انفرااسٹرکچر کھڑا کرے، تو دیش کا کتنا بھلا ہوگا؟ لیکن، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا، جبکہ یو.کے.، فرانس، جاپان، چائنا، یو.ایس.ایس.آر. کے سارے ملک، سنگاپور اور ملیشیا میں اس کو accept کر لیا ہے۔ اگر آپ اسلامک بینکنگ سے گھبراتے ہیں، تو اسے آپ Alternative banking system بناکر کر دیجئے۔ اس سے آپ کو اتنا فنڈ ملے گا کہ آپ اپنے بارھویں پلان میں کافی پیسہ لگا سکیں گے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے experts، جن میں ہمارے آنریبل پروفیسر سوامی ناتھن جی بھی تھے، جو کہ یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی اور لوگوں کے ساتھ recommend کیا کہ فنڈ لانے کا یہ بھی ایک alternative ہو سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس طرف کوئی دھیان نہیں جا رہا ہے۔ جیسے ہی اسلامک نام آتا ہے، تو ایک دم خوف آتا ہے کہ کہیں یہ آتنک وادیوں کا پیسہ تو نہیں آئے گا؟ آپ اسے اپنے بینکوں میں رکھیے اور اس کا نام رکھہ دیجئے۔ آپ اس کو alternative banking کر دیجئے، اس کو بینک سے جوڑ دیجئے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم ایک ونڈو کھول دیجئے۔ آپ بنگلہ دیش، یو.کے. وغیرہ سب جگہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان کا جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے، وہ ایک دوسرے بینکنگ کے تھرو جا رہا ہے۔ مسلمان انٹرپرائز نہیں ہے، اس کا پیسہ 80 فیصد نون-مسلم یوز کرتے ہیں۔ ادروائز وہ ہندوستان کے ایک پورے خاکے میں پورے انفرااسٹرکچر میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی طرح رزرو بینک یا فائننس منسٹری کوئی توجہ نہیں کر رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت ہم کو وہ پیسہ ڈیولپ کرنا ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کی رپورٹ کہتی ہے کہ 1.5 ٹریلین ڈالر چاہئے اگلے پانچ سالہ منصوبے میں۔ ایک alternativeآپ کے پاس ہے۔ میں اس کے لئے برابر فائننس منسٹری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ alternative banking نہیں کھول سکتے ہیں تو کم سے کم ایک طریقہ یہ کیجئے کہ رزرو

بینک آف انڈیا یا اسٹیٹ بنیک آف انڈیا یا کسی بھی نیشنلائزڈ بینک میں ایک ونڈو کھول دیجئے، کیوں کہ اس علاقے سے مسلمانوں کا وہ پیسہ جو انٹرسٹ کے نام سے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، وہ utilize ہو جائے گا اور اس سے ملک کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ اس کو مانیٹر کیجئے اور ایک کمیٹی بنائیے، جس طرح سے رگھوراجن صاحب نے کہا اور دوسرے لوگوں نے کہا، میرے پاس پوری لسٹ ہے ہندوستان اور دنیا بھر کے لوگوں کی، جنہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہی ایک alternative بنتا ہے اور اس کا یوروپ فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن امریکہ نہیں چاہتا. اسلئے کہ امریکہ کا جو سسٹم ہے اس کو نقصان ہوگا، جو مڈل ایسٹ میں ہمارے ہندوستانی رہتے ہیں اور جو دنیا بھر میں ہمارے ہندوستانی رہتے ہیں، ان کا پیسہ بھی ہندوستان میں اس طریقے سے اس بینکنگ سسٹم میں آ جائے گا، جس سے ہم کو اگلے بجٹ یا اگلے پانچ سالہ منصوبے میں فائدہ ہوگا! اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ فائنینس منسٹر صاحب کو اس پر توجہ دینی چاہئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس پر ضرور کوئی نہ کوئی ذمہ داری سے جواب دیں گے، کیوں کہ ونڈو کھولنے کے بعد پھر آپ ایک کمیٹی بنا دیجئے اور اس کو دیکھئے کہ اگر اس کو اس میں کچھ ترمیم کرنا ہے تو اس کو دیکھئے، مانیٹر کرئیے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہمارے بینکوں میں لوگ پیسے نہیں ڈال رہے ہیں۔ آپ جاکر دیکھئے کہ یہ پیسہ گھروں میں پڑا ہوا ہے، بلیک منی کی شکل میں پڑا ہوا ہے. یہ سب کا سب پیسہ وائٹ ہو جائے گا اور جب وائٹ ہوگا تو اس سے دیش کا کتنا بھلا ہوگا اور کتنی اس کی ضرورت پڑے گی.

اس کے علاوہ اس بجٹ کے سلسلے میں، میں دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ پرسنل لاء بورڈ نے دو سفارشیں کی تھیں. ایک، یہ کہا تھا کہ ڈائریکٹ ٹیکس ریلیجئس پلیسز کو آپ ختم کر دیں، اس کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے. دوسری ان کی سفارش یہ تھی کہ آر.ٹی.ای. کو سیپریٹ کریں مائنارٹیز انسٹی ٹیوشن سے. اس کی بھی کوئی سفارش نہیں ہے.

[श्री मोहम्मद अदीब]

تیسری بات، جو میں اتر پردیش کے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش آج بہت پچھڑ گیا ہے، اس کو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، وہاں بجلی اور سڑکوں پر پیسہ لگانے کی ضرورت ہے۔ اترپردیش میں کافی بڑی تعداد میں آلو کا پروڈکشن ہوتا ہے۔ اس بجٹ میں، میں فائنینس منسٹر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیہاتوں میں کولڈ اسٹوریج اور پروسیسنگ یونٹ کے لئے مزید پیسے کا انتظام کریں اور اگر اترپردیش کھڑا ہوگا تو یہ دیش بھی کھڑا ہو جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔]

SHRIMATI HEMA MALINI (Karnataka) : Hon. Vice-Chairman, Sir, I am glad to participate in the discussion on the General Budget presented by the hon. Finance Minister for 2012-13. A lot about it has been spoken by the Members not only in this august House, but also in the media, newspapers, in deliberations and lectures given by dignified professionals of our country. I will not go into the details as the time is very limited and my colleagues have already spoken a lot on many other subjects. I am going to concentrate only on art, culture and film industry.

महोदय, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की हिफाजत करना हमारी संस्कृति में विश्वास करने वाले हम सभी भारतीयों का दायित्व है, कर्तव्य है।

महोदय, भारत एक विशाल देश है जिसकी विविधता में एकता का दर्शन होता है। यहां अनेकों भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। इस बजट में देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए कोई विशेष योजना घोषित नहीं की गयी है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सांस्कृतिक विविधताओं को शामिल किया गया हो? क्या भारत दर्शन की कल्पकता भारत सरकार के पास है जिसमें लोक संस्कृति, लोक गीत, लोक महोत्सव से लोक संपर्क किया जाता हो? आज लोक महोत्सव में कमी आ रही है। चाहे आदिवासी नृत्य हो या शास्त्रीय नृत्य-जैसे ओडिसी, भरतनाट्यम, कत्थक आदि, इन सब में कमी हो रही है। जाहिर है, इससे लोक संस्कृति का कमजोर होना ही माना जाएगा।

महोदय, मैं यह सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं इस कला क्षेत्र से जुड़ी हुई हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन का प्रत्येक सदस्य संस्कृति का उपासक है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसकी लोक संगीत, लोक गीत या लोक नृत्य में रुचि न हो। देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि बहु-आयामी सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की जाए। इस बजट में क्या इसके लिए कोई प्रावधान किया गया है?

As per the Vision of the Ministry of Culture, "Culture represents a set of shared attitudes, values, goals and practices. A country as diverse as India is symbolized by the plurality of its culture. The mandate of the Ministry of Culture is to preserve and promote all forms of art and culture." But, the question is, whether the Government of India is caring and nurturing the Ministry of Culture as per its Vision.

The answer is: certainly, not. This is reflected in the Budget for 2012-13 presented by the hon. Finance Minister.

But, unfortunately, the Ministry of Culture has gained marginally in the Budget for 2012-13 with an outlay of Rs. 1,447 crores against Rs. 1,378 crores in the previous year of 2011-12. This is a marginal increase of Rs. 67 crores.

As per the department-wise break-up of the provisions, Rs. 415 crores has been allocated for overall promotion of art and culture. This is ridiculous.

Sir, culture in our country needs a lot more infrastructure and money. The spending capacity of some of the institutions is limited and they require a massive renovation. However, there has consistently been a very low allocation for culture under the successive Budgets.

The archaeological surveys, archives and museums have an outlay of Rs. 785 crores while libraries have Rs. 121 crores. However, the zonal cultural centres have been allocated miserably Rs. 31 crores. The National School of Drama has an outlay of Rs. 23 crores, which is' a small hike from Rs. 21 crores last year. We need centres for performing arts in smaller cities and more private-public-partnerships in culture. We have a lot of professionally trained people at the National School of Drama, but many of them are jobless today.

Young artists cannot afford gallery, auditorium and other spaces to display their art and performance, because auditorium and other places are expensive. The Government needs to build multi-disciplinary art centres across the country to promote culture.

I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister to find out what the Ministry of Culture has done with the funds allocated to it for the last 2-3 financial years.

On the one hand, many institutions which are promoting art and culture with full dedication are in need of funds and, on the other, every year the Ministry of Culture lets crores of rupees lapse in the national coffers.

Sir, the CAG Report of 2009-10 states that of Rs. 1,296 crores allocated to it that year, the Ministry of Culture returned Rs. 111 crores. Similarly, Rs. 99 crores was surrendered in 2008-09 and Rs. 96 crores in 2007-08.

The Budgetary process begins in December with institutions forwarding their demands to the Ministry of Culture, which then forwards it to the Ministry of Finance.

In the Budget Session, the Parliament votes on these demands. After several months of such debates, usually close to a year, the Ministry of Culture receives the

[SHRIMATI HEMA MALINI]

funds, which it, then, allots to the institutions that asks for them. However, since the institutions are in a state of inertia by then, no action is taken and the funds lapse.

Now, Sir, I would like to say a few things about my film industry. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : You can take, at the most, two more minutes.

SHRIMATI HEMA MALINI : Okay, Sir. Being in the film industry for several years, I, on behalf of media fraternity, covering films, TV ads, etc, would like to put one question to the hon. Finance Minister. Has anybody from his department taken pains to enumerate revenue earned by the Government via direct and indirect taxes from entire India and the overseas business from film industry? Our members, including artists, technicians and unskilled people, work day and night and entertain all and thereby bring some solace in the life of the, as you say it, *aam aadmi.* But we are treated worse than an *aam aadmi.*

The film industry generates huge amount of revenue to the Government. But it has got no place in the Budget Speech of the hon. Finance Minister. Today, our fraternity has reached at peak. The entire world is looking upon us. Various international film companies are ready to come and work here. Our people are demanding that the film industry should be given full industry status so that we can overcome some administrative hurdles, like, shooting abroad, getting financial support, overcoming visa problems, foreign tours, etc. But in spite of generating huge revenues, we are even lacking some of the basic facilities, which we are in dire need of. A lot of corporate houses are entering in the film industry to help out, but without an 'industry status', our fraternity as well as corporate houses are helpless to do anything. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Conclude please.

SHRIMATI HEMA MALINI : Sir, I would also like to mention here about the increase in the customs duty and excise duty on gold. A lot of hue and cry is being made against this increase. The gold price, today, is already very high. It is about Rs. 2800/- per gram. The new Budget levies duty on import of gold, which will make the gold more expensive, as compared to anywhere else in the world. The excise duty on non-branded jewellery will also make it even more expensive than other countries. So, the consumers will be adversely affected. They will have to pay Rs. 1000, per gram, extra. Overall, the jewellery trade will also be affected tremendously. And, India, being the highest consumer of gold, will start looking at other countries to buy jewellery, like, Dubai, etc. It will also promote smuggling.

It is my utmost demand to the hon. Finance Minister that the film industry should be given 'full industry' status. The Ministry of Culture should not return funds allocated to it. Rather, it should help and provide support to the genuine institutions which are promoting art and culture in our country.

Thank you very much, Sir.

श्री नरेन्द्र बुढानिया (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष जी, इस समय हमारा देश बहुत सी चुनौतियों को मुकाबला कर रहा है और जिन परिस्थितियों में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2012-13 का बजट पेश किया है, उनमें इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और इस बजट का दिल से समर्थन करता हूं।

महोदय, यह बजट UPA सरकार की पिछली नीतियों को तेज गति देने वाला बजट है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर सभी को शामिल किया गया है। भारत के हर क्षेत्र को, हर सैक्टर को, हर राज्य को, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को इसमें शामिल किया गया है और ऐसा कोई वर्ग नहीं है, जिस पर इसमें ध्यान न दिया गया हो।

महोदय, बजट प्रस्तुत करते समय हमारा GDP growth rate 7.6 percent था। आज पूरे विश्व में महंगाई और मंदी का दौर चल रहा है। यदि हम दूसरे देशों का average growth rate देखें, तो वह करीब 3.3 या 4 परसेंट के करीब आता है, जो हमारे देश की तुलना में 5 परसेंट कम है।

महोदय, कृषि के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया है और हमारा ग्रोथ रेट बढ़कर 2.5 तक पहुंच गया है। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ज़रूर आशा के अनुरूप नहीं बढ़ा है और हम 4.5 तक ही पहुंचे हैं, लेकिन जो बजट पेश किया गया है, इससे लगता है कि आने वाले समय में हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी चिंता budgetary deficit की तरफ ज़रूर है, लेकिन जहां तक मैंने बजट का अध्ययन किया है, यह deficit ऐसे प्रोग्राम्स को लेकर है, जो आम जनता तक पहुंचते हैं। चाहे हमारी flexi schemes हों जिनमें हमारे 1 लाख 66 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और चाहे subsidy का मामला हो। आज हम लोग food subsidy उपलब्ध करा रहे हैं, petroleum subsidy उपलब्ध करा रहे हैं और fertilizers पर भी subsidy उपलब्ध करा रहे हैं। Fertilizer एक बहुत बड़ा subject है, जो किसानों से जुड़ा है। आज हम 61 हज़ार करोड़ की subsidy किसानों को दे रहे हैं। इस बार वित्त मंत्री जी ने और यू.पी.ए. की सरकार ने फैसला किया है कि पहले जो पैसा होता था, वह कारखानों के मालिकों के पास जाता था, लेकिन इस बार यह सीधे किसानों के पास जाएगा, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, आज आम आदमी को रोटी चाहिए, खाना चाहिए और इसकी तरफ यू.पी.ए. सरकार ने बहुत ध्यान दिया है और एक बड़ा निर्णय Food Security Bill के रूप में लिया है, जो हमारी संसद में पेश हुआ और अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास है। इसके लिए आज मैं तहेदिल से हमारी यू.पी.ए. की अध्यक्षा आदरणीया सोनिया गांधी जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आम गरीब आदमी की तरफ उनकी नज़र गई है और एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है।

महोदय, इस बजट पर जब हम चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा कृषि सेक्टर, जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारी यू.पी.ए. सरकार की नीतियों की वजह से ही हमने 2011-12 में ढाई सौ मिलियन टन अनाज पैदा किया। हमारा 2011-12 का जो लक्ष्य था, वह 239 मिलियन टन था, लेकिन हमारे किसानों को हम तहेदिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे अनुमान से आगे बढ़कर, अपनी मेहनत से यह काम पूरा किया। हमारी जो उम्मीद 2020 तक की थी, वह उन्होंने इसी साल पूरी कर दी।

[श्री नरेन्द्र बुढानिया]

महोदय, आज हम कह सकते हैं कि हम अनाज के ऊपर आत्मनिर्भर हैं। हम बहुत गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि पहली हरित क्रांति भी हमारी देन थी और आज जो हम आत्मनिर्भर हुए हैं, यह भी यू.पी.ए. सरकार की देन हैं, उसकी नीतियों का परिणाम है। आज हमने दालों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। जहां हम दालों में 14-15 मिलियन टन से आगे नहीं बढ़ पा रही थे, हमें खुशी है कि हम 18 मिलियन टन तक पहुंचे हैं, जिससे हमारे आयात में कमी आएगी। बागवानी के क्षेत्र में भी हम 250 मिलियन टन तक पहुंच चुके हैं। मैं वित्त जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में कृषि का विशेष ध्यान रखा है। किसानों की पीठ थपथपाने के लिए, किसानों को लाभ देने के लिए उन्होंने 1 हजार करोड़ रुपए के ऋण की बढ़ोतरी की है - 4.75 लाख से बढ़ाकर 5.75 लाख रुपए और वह भी 7 प्रतिशत की सस्ती ब्याज दर पर। यदि किसान समय पर जमा कराए, तो 3 प्रतिशत की और छूट देकर, 4 प्रतिशत पर किसानों को यह ऋण मिलेगा।

महोदय, हम पूर्वी राज्यों के रास्ते दूसरी हरित क्रांति की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बजट के अंदर 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

मैं यहीं सुन रहा था, सब कह रहे थे कि यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, लेकिन मैं हमारे पूर्वी किसानों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की तथा 2011-12 में सात लाख मिलियन टन अधिक अनाज पैदा किया। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने चार सौ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए रखे हैं। **(समय की घंटी)**

महोदय, इस बजट के अंदर कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई का भी विशेष ख्याल रखा गया है। विशेष तौर से माइक्रो इरीगेशन के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। आज कृषि के अंदर निवेश होना बहुत जरूरी है। आज कृषि में निवेश की कमी है। प्राइवेट निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सिंचाई के लिए बांध, टर्मिनल मार्किट, soil-testing tab आदि की स्थापना करने की प्राथमिकताएं सुनिश्चित की हैं। इन प्रयासों से यूपीए सरकार का जो अनुमान है कि ग्रोथ रेट चार प्रतिशत होना चाहिए, वह प्राप्त किया जा सकेगा।

महोदय, मैं किसान का बेटा हूं, राजस्थान से चुनकर आया हूं इसलिए राजस्थान के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जो निरंतर प्राकृतिक आपदाओं और चुनौतियों का सामना करता रहता है। वहां पर बराबर अकाल पड़ता है, कभी वहां ओले गिर जाते हैं, ओला वृष्टि हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी पाला पड़ जाता है...।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अब समाप्त करें। चार बजे रिप्लाई होना है।

श्री नरेन्द्र बुढानिया : हमारा किसान इन सबका मुकाबला कर रहा है। आज वह आपकी तरफ देख रहा है। वह सबकी तरफ देख रहा है कि आज राजस्थान के गरीब लोगों की पीठ थपथपाने की आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता चाहता हूं कि वे राजस्थान को विशेष दर्जा देकर पीने के पानी और बिजली के लिए उन्हें विशेष सहायता दें। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

उपासभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अब बस कीजिए। आठ मिनट हो गए हैं।

श्री नरेन्द्र बुढानिया : अंत में, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। राजस्थान में प्रचुर मात्रा में कच्चा तेल निकल रहा है। आज राजस्थान रिफाइनरी चाहता है। रिफाइनरी के लिए हम काफी लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं। हम आदरणीय सोनिया गांधी जी को, आदरणीय प्रधान मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और पेट्रोलियम मंत्री जी को बराबर मिलते रहे हैं। मैं पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट के अंदर, राजस्थान का जो बजट आया है, उसमें उन्होंने वे सारी बाते मानी हैं, जो रियायतें देनी हैं, उन सब रियायतों को माना है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर

रिफाइनरी स्थापित की जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : श्री राम कृपाल यादव। आप दस मिनट से ज्यादा समय मत लीजिएगा। क्योंकि चार बजे रिप्लाई होना है इसलिए मैं सबका समय काट रहा हूं।

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बजट पर चर्चा की अनुमति दी। महोदय, बजट आने के पहले ऐसा लग रहा था कि माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी जी एक अनुभवी राजनेता के रूप में रहे हैं और वित्त मंत्री के रूप में कई बार उनको देश की सेवा करने का मौका मिला है-अब फिर कर रहे हैं-इसलिए वे आम लोगों को कुछ रियायत देने का काम करेंगे। लेकिन इस बजट को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के आम लोगों को निराशा हाथ लगी है-चाहे वे खेत-खलिहान में काम करने वाले लोग हों, बेरोजगार हों या नौजवान हों-सब लोगों को निराशा हाथ लगी है। खास तौर पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो आयकर की सीमा 1 लाख 80 हजार से बढ़ाकर मात्र 2 लाख रुपए की है, उससे लोगों को काफी निराशा हुई है। कोई खास नहीं, केवल बीस हजार रुपए की बढ़ोत्तरी करके आकयर में छूट दी गयी है, जिससे आम लोगों के प्रति वर्ष 2000 रुपए का मुनाफा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत चालाकी के साथ उत्पाद कर और सेवा कर में दो-दो परसेंट की बढ़ोत्तरी कर दी और लोगों के सारे आरमानों पर पानी फेरने का काम किया है। बढ़ोत्तरी देखने में तो दो परसेंट लगती है, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक पैमाने पर होने वाला है।

इससे देश में हर चीज़ की कीमत मे बढ़ोत्तरी हो जाएगी। महंगाई की मार से देश की आम जनता पहले से ही जूझ रही है, संघर्ष कर रही है लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया कि हम अब महंगाई कम करेंगे ओर लोग इस आशा में थे कि उन्हें इस बजट से कुछ राहत मिलेगी और महंगाई कम हो जाएगी। इस बजट में जो 2 प्रतिशत उत्पादक कर, सेवा कर बढ़ाया गया है, इससे हर चीज़ के दाम में अपने आप बढ़ोत्तरी हो जाएगी। अभी पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने वाले हैं, अगर पेट्रोलियम पदार्थो कि दाम पुन: बढ़ेंगे, तो इसका कुप्रभाव देश के अवाम पर पड़ेगा। जो लोग खेत और खलिहान में काम करते हें, जो मजदूर हैं, जो नौजवान हैं, उन सब पर इसका असर पड़ेगा। लोगों में सरकार के इस बजट से निराशा उत्पन्न हुई है। हमारा ग्रोथ रेट लगातार कम हो रहा है, यह भी देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि गरीबों की संख्या घट रही है, गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों की संख्या घट रही है, मगर मैं समझता हूं कि यह व्यावहारिक रूप से ठीक नहीं है। मैं बिहार से आता हूं और उसमें पिछले साल 50 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे थे, उसमें बढ़ोत्तरी हुई है और मैं समझता हूं कि यह बढ़ोत्तरी पूरे देश में बड़े पैमाने पर हुई है।

महोदय, मैं समझता हूं कि आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी फैल रही है। हमारी आत्म-निर्भरता खेती पर निर्भर है। हमारे देश में खेत और खलिहान पर निर्भरता तब तक नहीं घटेगी जब तक कि इस देश में उद्योग का जाल न बिछे। जब उद्योग पर निर्भरता बढ़ेगी तब खेत पर निर्भरता कम होगी और तभी इस देश से गरीबी कम हो सकती है। इस देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है। यह सरकार खेत और खलिहान में काम करने वाले लोगों को समुचित सुविधा नहीं दे पा रही है। यह और बात है कि सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। सरकार का कमिटमेंट इस बजट में है और इससे पहले भी है कि हम पिछड़े इलाकों पर विशेष ध्यान देने का काम करेंगे। इस देश में जो पिछड़े इलाके हैं, चाहे इसमें हमारा प्रदेश बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे ओडिशा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इसके अलावा कई और इलाके हैं जहां पर स्थिति ठीक नहीं है। हमारे देश में लोगों की खेत और खलिहान के प्रति रूचि घट रही है। यह शुभ संकेत नहीं है। अगर लोगों की खेत और खलिहान के प्रति रूचि घटेगी, तो हमें दो वक्त की रोटी मिलनी भी दुर्लभ हो जाएगी। हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन खेत उतने के उतने ही हैं। हमारी निर्भरता खेत पर ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उद्योग कम हो रहे हैं। आमतौर पर जो रोजगार के अवसर हैं, उनमें भी कमी आ रही है। आज खेत और खलिहान में काम करने वाले

[श्री राम कृपाल यादव]

किसान निराश हैं। वे आत्म-हत्या क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी हमें बारीकी से देखना पड़ेगा। अभी खाद की कीमतें आसमान छू रही हैं, डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है, सिचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है और इस बजट में सरकार के बेचारे किसानों को कोई राहत देने का काम नहीं किया है। किसानों को जो बैंक से ऋण मिल रहा है, उस ऋण पर ब्याज बहुत ज्यादा है। इसलिए किसान परेशान हैं।

सर, ऋण लेने की जो प्रक्रिया है, वह बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसके कारण आम किसानों को बैंकों से ऋण लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। किसान बड़े-बड़े लोगों से कर्ज लेकर खेत में उत्पादन कर रहे हैं। अभी हमारे साथी बता रहे थे और यह बात सही है कि पूरे देश में धान का उत्पादन काफी हद तक बढ़ा है, मगर उनको मार्केटिंग नहीं मिल रही है। हमारे देश में गोदाम नहीं हैं और गोदाम की सुविधा नहीं होने की वजह से जो बिचोलिए हैं, जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, वे सस्ते रेट में धान को खरीदकर किसानों का exploitation कर रहे हैं।

सरकार ने FCI के माध्यम से क्रय केन्द्र खोल रखे हैं, लेकिन वे अपर्याप्त हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में सरकारी रेट से 1100 रुपए पर धान की खरीद हो रही है। जो क्रय केन्द्र के FCI के कर्मचारी थे, उन्होंने लोगों से असहयोग किया और उनकी वजह से किसान को कम कीमत पर अपना धान बेचना पड़ा। जहां उनको 1100 रुपए का रेट मिलना चाहिए था, वहां उन्हें 400-500 रुपए में धान बेचना पड़ा, क्योंकि उनके पास रखने का साधन नहीं था। महोदय, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम गोदामों को बनाने का काम करेंगे। जब तक गोदाम नहीं बनेंगे तब तक इसी तरह से किसानो का exploitation होता रहेगा, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह देश में हरित क्रांति लाने में सहयोग करना चाहती है, खासतौर से जो पूर्व-उत्तर के राज्य हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल है, बिहार है और यूपी है। अगर आप चाहते हैं कि वहां हरित क्रांति आए, तो आपको निश्चित तौर पर विशेष फंड देने की जरूरत है। आपने पहले 400 करोड़ किया था अब आपने उसको बढ़ाकर 1,00 करोड़ रुपया कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह रुपया इसके लिए नाकाफी है। सर, किसानों के प्रति हरित क्रांति हेतु 1,000 करोड़ रुपया नाकाफी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि अगर आप सही मायनों में हरित क्रांति चाहते हैं, किसानों में खुशहाली लाना चाहते हैं तो जो पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से लगे इलाके हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सर, बिहार में क्या स्थिति है, वहां एक तरफ बाढ़ है तो एक तरफ सुखाड़ है। यह नेपाल से लगता हुआ स्टेट है, इसलिए जब बाढ़ आती है, तो अरबों रुपयों का नुकसान हो जाता है। वहां के लोग तो खेतों पर निर्भर हैं। हर साल बाढ़ में हजारों रुपयों का इंफ्रास्ट्रक्चर बह जाता है। सरकार पूंजी लगाती है, वह सब बाढ़ में खत्म हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को निश्चित तौर पर बिहार और बिहार जैसे पिछड़े इलाकों की ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां लोग खेतों पर निर्भर हैं। बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार की माली स्थिति और भी खराब हो गई है। वहां पर बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। जिस प्रदेश में बिजली का ठीक से उत्पादन नहीं होगा तो उसका विकास कैसे हो सकता है? **(समय की घंटी)** वैसे यह और बात है कि वहां के मुख्य मंत्री हर रोज दावा करते हैं कि बिहार देश के सबसे बड़े प्रदेश के रूप में हो गया है, लेकिन सही स्थिति यह है कि वहां की स्थिति बद से बदतर है। सरकार से कई वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि बिहार सरकार के प्रति आपका रवैया ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**... आप विशेष पैकेज देने का काम कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप खत्म कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं खत्म कर रहा हूं और एक या दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आप मुझे को-ऑपरेट कीजिए क्योंकि मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जहां भुखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, बदहाली है और अशिक्षा है। वहां दयनीय स्थिति है, इसलिए आप थोड़ा तो को-ऑपरेट कीजिए। आप दो-चार, पांच मिनट बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस पर सदन की सहमति है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो पी.जे. कुरियन) : राम कृपाल जी, चार बजे reply होना है।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं वहां की स्थिति बताना चाहता हूं कि वहां पर कोई उद्योग नहीं है। वहां पर सिर्फ खेतों पर काम करना होता है। केन्द्र सरकार का रुझान खेतों की ओर नहीं है, इसलिए केन्द्र सरकार इस ओर ध्यान दे।

सर, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि सरकार अभी बहुत दावा कर रही है कि हमने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। यह बात सही है कि सर्वशिक्षा अभियान से असर हुआ है। इस देश में शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन उसके क्या हाल हैं? मैं आपको बताता हूं कि कल ही एक रिपोर्ट छपी है। मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं, "शिक्षा का अधिकार RTE Act लागू होने के बावजूद देश में प्राथमिक शिक्षा की तस्वीर नहीं सुधर रही है। प्राइमरी में ड्रॉप आउट कम होने के बजाए बढ़ रहा है। 2009-10 में चार करोड़ बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी।" मैं आपको यह स्थिति बिहार की नहीं, बल्कि पूरे देश की बता रहा हूं, बिहार में यह सबसे अव्वल दर्जे पर है।

बिहार में 2009-10 में 44 प्रतिशत छात्र और 41 प्रतिशत छात्राओं ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई छोड़ देने का काम किया है। सर, यह बिहार की स्थिति है। क्या आपको पता है कि बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? यह इसलिए है क्योंकि उनके पास दो वक्त के खाने का भोजन भी उपलब्ध नहीं है। वे क्या करेंगे? वे उनसे काम लेंगे। यह जो स्थिति है, यह पूरे देश में है। सर, ऐसा कई प्रदेशों का हाल है, यह यू.पी. का हाल भी है। मेरे पास उत्तराखंड, झारखंड और दिल्ली के आंकड़े हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को निश्चित तौर पर इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे बिहार में अभी-भी 8000 स्कूल भवनहीन हैं, जहाँ पर बच्चे छत के नीचे पढ़ रहे हैं। वहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? आप वहाँ चले जाइए, पूरे देश के पैमाने पर चले जाइए ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Ram Kripalji, please conclude.

श्री राम कृपाल यादव : सरकार ने राजीव गाँधी हेल्थ मिशन के माध्यम से पैसा दिया है ...**(व्यवधान)**... सर, मैं खत्म कर रहा हूं ...**(व्यवधान)**... Sir, I am going to conclude. Please, cooperate with me. मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। सर, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि स्वास्थ्य सेवा बेसिक चीज है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आज बच्चों को, आम आदमी को स्वास्थ्य सेवा से निराशा हो रही है। कई ऐसे लोग हैं, जो बिना इलाज के मर रहे हैं। आज सभी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह प्राइवेट संस्था में जाने का काम करे। हमारे यहाँ एम्स खुल रहा है, अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, मगर पूरे देश और बिहार में स्वास्थ्य सेवा के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का काम कीजिए ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप बाकी के प्वाइंट्स फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी में लिखकर दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम कृपाल यादव : सर, चिट्ठी तो मैं लिखते-लिखते थक गया हूं ...**(व्यवधान)**... किंतु यह सरकार है कि सुनती ही नहीं है ...**(व्यवधान)**... सर, यह लगातार हो रहा है ...**(व्यवधान)**... सर, मैं अंत में लास्ट प्वाइंट कहना चाहता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि अगर बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश पर ध्यान नहीं देंगे, किसानों पर ध्यान नहीं देंगे, मजदूरों पर, बेरोजगारों पर, नौजवानों पर ध्यान नहीं देंगे, तो कुछ नहीं होगा। ये आपकी ताकत है, इस ताकत के आधार पर देश आगे बढ़ेगा, इसलिए आपको इन पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको बजट में इनके लिए पर्याप्त राशि का प्रबंध करना पड़ेगा।

मैं सबसे लास्ट में कहना चाहता हूं कि देश में भ्रष्टाचार की जो बड़ी समस्या है, इस भ्रष्टाचार की वजह से आज पूरा देश उद्वेलित है, परेशान है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम काले धन के लिए श्वेत-पत्र लाएंगे, तो आप लाइए ...**(व्यवधान)**... देश से भ्रष्टाचार को दूर कीजिए, इच्छाशक्ति रखिए, नहीं तो आने वाले दिन ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : हो गया है ...**(व्यवधान)**... Now, Dr. Vijaylaxmi Sadho.

श्री राम कृपाल यादव : सर, आने वाले दिन इस देश के लिए ठीक नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**... आप, किसान को, मजदूर को ताकत दीजिए ...**(व्यवधान)**... और जो बिहार जैसा पिछड़ा इलाका है ...**(व्यवधान)**... उसको मजबूती प्रदान कीजिए ...**(व्यवधान)**... अन्यथा सरकार कितना कुछ भी कर ले, जब तब आप पिछड़े इलाकों को न्याय नहीं देंगे, तब तक आप बिहार ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now, Dr. Vijaylaxmi Sadho. Ram Kripalji, it is not going on record. आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

श्री राम कृपाल यादव :*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Ram Kripalji, it is not going on record. आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

श्री राम कृपाल यादव :*

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : धन्यवाद। आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... Now, Dr. Vijaylaxmi Sadho. Please, do not take more than ten minutes.

डा विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश) : सर, यह बताइए कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं?

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : बोलिए, लेकिन दस मिनट बोलिए।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर टेन प्लस फाइव मिनट्स।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे कुरियन) : उनका टाइम भी ऐड करके बोला है।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ जो संतुलित बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। कठिन अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू आर्थिक स्थितियों के बावजूद हमारे सामने एक संतुलित बजट है। वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह वास्तविकता के बहुत नजदीक है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कल माननीया श्रीमती प्रभा ठाकुर जी ने बहुत सही कहा था कि पहले ये स्थितियां हुआ करती थीं कि किसान फटे हाल था, फटे कपड़े पहनता था, महिलाएं दो साड़ी में अपना साल निकालती थीं, किसान की वह पगड़ी, जो उसके सिर का मान होती थी, उसमें छेद होते थे आदि। यहाँ कई बातें उठीं कि इस देश में बहुत वर्षों से कॉंग्रेस की सरकार रही है, क्या किया, क्या नहीं किया।

यहाँ विरोधात्मक शब्द आए, बाहर भी चले, लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूँ कि देश की आजादी में किसका योगदान था, देश की आजादी के बाद के नवनिर्माण में किसका योगदान था, इस देश में हरित क्रांति कौन लाया? इस देश में ...**(व्यवधान)**... वह तो पूरा देश जानता है माया सिंह जी, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश में प्रिवी पर्स किसने खत्म किया, इस देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से गरीबों के लिए, गरीब किसान के लिए बैंकों के दरवाजे किसने खोले? ...**(व्यवधान)**... इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी कौन लाया? ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Don't do that. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... प्रभात जी, आप बैठिए। Mayaji, we have no time. ...(*Interruptions*)... You address the Chair.

---

* Not Recorded

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : उपसभाध्यक्ष महादेय, मेरे समय में कटौती नहीं की जाए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश मे गरीबों की आर्थिक अवस्था में सुधार करने के लिए स्वर्गीय राजीव गाँधी ने पंचायती राज के माध्यम से निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने की परिकल्पना की। यह किसने किया? यह हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा था कि मेरे विचार में हमें जो सबसे पहला कार्य करना चाहिए, वह यह है कि हम अपने सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों पर दृढ़ रहें। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब आर्थिक व्यवस्थाएँ ठीक होंगी, तो सामाजिक व्यवस्थाएँ अपने आप सुदृढ़ होंगी। आर्थिक व्यवस्था का बीड़ा उठाया स्वर्गीय राजीव गाँधी ने। स्वर्गीय राजीव गाँधी ने संविधान में 73वें और 74वें संशोधन किए। मुझे यह नहीं कहना चाहिए, मैं सभा के अन्दर बहुत बाद में आई हूँ, लेकिन उस वक्त इसका विरोध किसने किया था, इसको भी याद करना चाहिए। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि पंचायती राज की परिकल्पना, जो स्वर्गीय राजीव गाँधी ने की थी, वह सरकार हो। स्वर्गीय राजीव गाँधी चाहते थे कि निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी हो, महिलाओं की सत्ता में भागीदारी हो, योजनाएँ दिल्ली से नहीं बनें, योजनाएँ प्रदेश की राजधानियों से नहीं बनें, बल्कि ग्राम पंचायत में बैठे हुए व्यक्ति योजना बनाएँ। ...**(व्यवधान)**...

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि राज्य सभा एक थिंक टैंक है। यहाँ चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मैं बहुत छोटी हूँ, बाद में आई हूँ, लेकिन मैंने सुना कि राज्य सभा एक थिंक टैंक है, यहाँ चिंतन होता है, मनन होता है, यहाँ योजनाएँ बनती हैं, योजनाएँ बाहर निकल कर जाती हैं और बाहर बैठा हुआ व्यक्ति यह सोचता है कि इस भवन से मेरे हित की कौन सी चीजें आएँगी, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि किस तरह से विरोधात्मक बातें आईं। विरोध होना चाहिए, यह हमारे प्रजातंत्र की स्वस्थ परम्परा है, लेकिन विरोध में सुझाव भी होना चाहिए। हमारे प्रभात झा जी ने कल भाषण दिया। मैं सोचती थी कि वे पत्रकार हैं, एक प्रदेश में, जहाँ से मैं आती हूँ, उस सरकार के संगठन के मुखिया हैं, मुझे लगा कि यहाँ कुछ सुझाव आएँगे, प्रदेश के हित के लिए कुछ बातें रखी जाएँगी, लेकिन कल उनका भाषण सुन कर मुझे लगा, क्योंकि 2013 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, मुझे ऐसा लगा कि उनका भाषण एक नुक्कड़ सभा में दिए गए भाषण से ज्यादा कुछ नहीं था।

आपने कहा ...**(व्यवधान)**... आपने कहा कि शरद पवार जी ने मुख्य मंत्री शिवराज सिंह जी की तारीफ की। माननीय गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वह हमारे शिवराज सिंह जी की तारीफ लॉ एंड ऑर्डर के प्रति भी करें। जो जनता की रक्षा करते हैं, जो जनता के रक्षक हैं, पिछले दिनों फरवरी में उनकी सरेआम हत्या हुई। नरेन्द्र कुमार, आईपीएस अधिकारी, उनकी हत्या हुई, आईपीएस अधिकारी के ऊपर हमला हुआ। मैं मध्य प्रदेश में खरगोन जिले से आती हूं, वहां सरेआम शराब माफियाओं ने एक कांस्टेबल की हत्या की और एक एएसआई अभी भी अस्पताल के अन्दर भर्ती है ...**(व्यवधान)**... पन्ना जिले के अन्दर एसजीएम ...**(व्यवधान)**... हत्या हुई।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : आप सम्माननीय सदन को गुमराह नहीं करें। मृत्यु ट्रॉली पलटने से हुई है। यह बात बिल्कुल गलत है।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : इसके ऊपर भी आदरणीय चिदम्बरम जी से मेरा निवेदन है कि माननीय शिवराज सिंह जी की तारीफ करें कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है ...**(व्यवधान)**...

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, बजट में होम मिनिस्ट्री के ऊपर भी पैसा दिया गया है।

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : किसानों को 100 रुपये अतिरिक्त दिए गए ...**(व्यवधान)**...

डा विजयलक्ष्मी साधौ : जी हां, मैं उसके ऊपर भी आ रही हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : No, no, you please addres the Chair. ...(*Interruptions*)... Address the Chair please. ...(*Interruptions*)...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : आप बात कर रहे हैं किसानों को 100 रुपये बोनस की और एक रुपये पर ब्याज की, लेकिन आप बात नहीं कर रहे 50,000 रुपये के कर्ज माफी की ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : You please address the Chair. ...(*Interruptions*)...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : आपके नेताओं ने 50,000 रुपये के कर्ज माफी की बात की थी और 50,000 रुपये में किसान डिफाल्टर हो गया है ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : You time is going to be over. ...(*Interruptions*)... You have got only three more minutes. ...(*Interruptions*)...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, उसको 16 प्रतिशत ब्याज देना पड़ रहा है। वह डिफाल्टर हो गया है ...**(व्यवधान)**... यही इनकी रीति और नीति है ...**(व्यवधान)**... ये एक रुपये पर ब्याज और 100 रुपये बोनस की बात कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude it now. ...(*Interruptions*)... Please conclude it. ...(*Interruptions*)... Please conclude it. ...(*Interruptions*)... That's over. ...(*Interruptions*)... Take your seat please. ...(*Interruptions*)... That is over now. ...(*Interruptions*)... Now, Shri Bhattacharya. ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सच बहुत कड़वा होता है ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude it now. That is enough. ...(*Interruptions*)... Take your seat please. ...(*Interruptions*)... Yes. Mr. Bhattacharya. ...(*Interruptions*)...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सच बहुत कड़वा होता है ...**(व्यवधान)**... सच बहुत कड़वा होता है ...**(व्यवधान)**... जब वे बोले थे, तब हमने विरोध नहीं किया था, लेकिन जब हम बोल रहे हैं, तब वे विरोध क्यों कर रहे हैं?

उपासभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : बैठिए-बैठिए ...**(व्यवधान)**... प्लीज़ ...**(व्यवधान)**... अभी रिप्लाई होना है ...**(व्यवधान)**... I have called Mr. Bhattacharya. ...**(व्यवधान)**...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर आप कहते हैं, तो मैं बैठ जाती हूं। थैंक्यू।

उपासभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अभी रिप्लाई होना है, इसीलिए कह रहे हैं। भट्टाचार्य जी, आप पाँच मिनट ले लें।

SHRI P. BHATTACHARYA (WEST BENGAL) : I am extremely happy that you have allotted five minutes' time. So, I can use only one sentence in support of this Budget. I congratulate the hon. Finance Minister. May I put if off ?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KUREIN) : That is up to you.

SHRI P. BHATTACHARYA : I congratulate the hon. Finance Minister for presenting an imaginative, growth-oriented, reform-oriented and a balanced Budget. I think this will go a long way in making our economy more stable.

Sir, the Budget is an instrument of income redistribution rather than a mechanism of allocation of resources. I consider the Budget 'balanced' in the sense that it has tried to address the concerns of different sections of the society, focusing on common man.

Sir, the best part of the macro economics management of our Finance Minister is that despite turmoil in the world economy, much lower direct tax collection than planned and increased burden of subsidies, he has achieved the GDP growth of 6.9 per cent in 2011-12 and has targeted a growth of 7.6 per cent in 2012-13. Despite all difficulties, it is commendable that he has contained the fiscal deficit at 5.9 per cent of GDP and pegged it at 5.1 per cent for 2012-13.

Sir, in a country suffering from pervasive poverty, hunger, malnutrition and illiteracy in the midst of all sorts of inequalities, I do not think that there could be a greater and better vision than addressing the concerns of common man. He has done a wonderful job of welfare of the disadvantaged and marginalized sections of the society along with a thrust on infrastructure, subject to the degrees of freedom available to the Finance Minister.

I would also congratulate him for being successful in bringing the inflation down by taking various measures.

Sir, the Budget 2012-13 is the first year of the Twelfth Five Year Plan of the Government. The Eleventh Plan was committed to securing an inclusive growth and, therefore, it was a turning point in the post-Independence economic planning of our country. Now, to take it forward, the Twelfth Plan is oriented at faster, sustainable and more inclusive growth. One of its main focuses being the streamlining and reducing the number of centrally-sponsored schemes along with better tracking and utilisation of funds.

Sir, this Budget has done a great job in the direction of fiscal consolidation by way of reorienting the subsidy disbursement methodology, which is directed towards better targeting and leakage-proof delivery of subsidies. The pilot projects were started last year and the same is being rolled out throughout the country. It is a well-known fact that majority of the subsidy was not reaching the targeted group and was squandered in the middle by the intermediaries and other groups. The direct transfer of subsidy to the beneficiary's account will go a long way in achieving the desired goals of the Government to uplift the life of the common man along with reducing the expenditure on subsidies as part of better macroeconomics.

[SHRI P. BHATTACHARYA]

4.00 P.M.

Sir, 1 want to compliment the Finance Minister for keeping emphasis on the majority of population of the country and enhancing the expenditure on all the plans covering rural areas. Sir, I would also like to compliment the Finance Minister for expanding the schemes on employment, skill development, financial inclusion and social security. Sir, through you, I would like to thank the Finance Minister for taking up the issue of arsenic pollution of water in West Bengal and earmarking Rs.50 crore for establishing a world-class centre for water quality with focus on arsenic contamination in Kolkata along with several other projects of research and creation of new knowledge.

Sir, lastly, the Finance Minister has shown great restraint by not pushing for the GST, which is a crowning glory in the initiatives of this Government in the words of economists. Instead, he has taken up the drafting of model legislation for the Centre and the State GST in concert with States. Thank you, Sir.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

SHRI P. KANNAN (Puduchery) : Sir, I am here to say a few words on the Budget presented by hon. Finance Minister Pranabda. It is very transparent in confessing and accepting the reality of the financial position of our country for which we must be very thankful to him for his sincerity. Without any inhibition or without any artificial excuses, he has put before the country something like a White Paper. Of course, he is going to present a White Paper on black money for which I am expressing my happiness on behalf of the nation.

The proposed Food Security Bill would be a boon to the common man and for this not just the Indian people but the whole of humanity would appreciate this achievement of the UPA Government. There is a saying 'food before philosophy'. A starving man can do nothing howsoever intelligent or knowledgeable or clever he may be. Food is a very important thing. It is the basic necessity of the human beings.

Mr. Deputy Chairman, Sir, through you, I want to make a request to the hon. Finance Minister. As I have been given a very short time, I don't want to have any dialogue or anything else, I straightaway come to the point. I request the Finance Minister to kindly consider the increase in excise duty and other things imposed on gold. Sir, I am not in support of gold price or gold jewellers or gold users or consumers. But, fortunately or unfortunately, in our country, gold is used by even the very common man. I have been told in Hindi that a *gareeb* cannot get his daughter married off without a little amount of gold. It may be five or ten sovereigns. Without that, there is no

marriage; there is no wedding. It is said that there is no dowry. But, definitely, gold must be there in a marriage, whoever it may be. So, I request you to consider it. I am not an economist at all. I don't know the repercussions but, on behalf of the people, I humbly request that the gold tax, or whatever it is, may be looked into. I hope you would do that.

Sir, growth is very important. The hon. Finance Minister, Pranabda, rightly said that without growth, what to distribute, whom to distribute, etc. We need to distribute to the needy. We are talking about equal distribution. Without growth, nothing can be done. (*Time-bell rings*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Kannan, please conclude.

SHRI P. KANNAN : So, we have to concentrate on growth. Apart from that, Sir, 1 totally support the Budget. The Finance Minister is an experienced and enlightened economist. He is the seniormost leader of our Government. I thank him that he has put all his experience in the interest of the nation and in the interest of the people. I once again thank you, Sir, for having given me time. Thank you.

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka) : Sir, I am raising a point which goes to the very root of the matter relating to our Parliamentary democracy. Sir, I am talking about the Unique Identification Authority of India Bill 2010. In the last Budget, I had said that the Unique Identification Authority of India Bill is a very, very serious matter which proposes to give *Adhar* numbers to not only 1.2 billions of Indian citizens, but also illegal immigrants. And, therefore, this is a serious matter. When the Bill is pending, by executive order, the thing is implemented and in the last Budget, an amount of Rs.1900 crore was allocated. I objected to that and pointed out that when the Bill is pending, you should not exercise executive power and spend huge sums of money. There was no reply by the Finance Minister. Then, I raised a Special Mention on 15th March 2011. I would read the operative part of it. It says, "Unless the Bill is considered by the Standing Committee and thereafter debated in both the Houses of Parliament and passed and becomes the law, the issue of *Adhar* numbers to the residents tantamounts to the circumventing of the Parliament by the Executive." Thereafter, I made my submissions to the Standing Committee. The Standing Committee observed, "The Committee are constrained to point out that in the instant case, since the law making is underway with the Bill being pending, an executive action is as unethical and violative of Parliament's prerogatives as promulgation of an ordinance while one of the Houses of Parliament being in session." Then, the Committee stated in its report, "The Committee regret to observe that despite the presence of serious difference of opinion within the Government on the UID scheme as illustrated below, the scheme continues to be implemented in an overbearing manner without regard to legalities and other social consequences."

[SHRI M. RAMA JOIS]

If our Constitutional provision that the Executive is responsible to the Legislature has any meaning, then implementation of that Executive Order must have stopped. They take a stand that the Executive power is co-extensive with that of the Legislature. They are totally misinterpreting that. As this provision affects the fundamental right of privacy under article 21 of the Constitution. Any law or regulation which affects the fundamental rights must be only by legislation and not by an Executive order, particularly when it is such a Serious provision involving enormous expenditure, involving thousands of crores of rupees from the exchequer.

There are serious articles written about this move. Let me quote an extract, "The Aadhar project, just as it failed in counterpart countries like the U.K., stands on a platform of mirage. India needs a mass campaign to express this." Another article says, "A spade is a spade." "The Aadhar project is directionless, ill-conceived, raises several questions on its efficacy and delivery." In spite of that, in the present Budget, the Finance Minister has not mentioned even the money. He says, "Enrolments into the Aadhar system have crossed 20 crores. The Aadhar numbers up-to-date have crossed 14 crores. I propose to allocate adequate funds to complete another 40 crore enrolments starting from April 1, 2012." How can an unidentified amount be stated in the Budget? There is stand taken by the executive to show the untenable stand of Executive before the standing Committee. It says, "If the Bill is not passed by any reason and if Parliament is of the view that the Authority should not function and express its will to that effect, the exercise would have to be discontinued." After this, why are you not bringing the Bill before the Rajya Sabha? The apparent reason may be that if the House rejects it, then there would be trouble. The next sentence is very curious, "This contingency does not arise." That means, the Parliament rejecting the Bill does not arise. That is the stand taken by the Government before the Standing Committee. Sir, it is most unfortunate. We maintain that our Constitution is functioning properly and all that. Thousands of crores of rupees have been spent. The provisions like Aadhar have been tested and rejected in the U.K., China, the U.S., and others. You are not having a public debate, not having a debate in Parliament; can you call this a democratic process?

My submission is, if Constitution has any meaning, then immediately stop spending on it. Already, thousands of crores of rupees have been spent. Suppose, the Bill is rejected, then what is going to happen? Are you going to surcharge anybody? It is a very serious matter, Sir. But, unfortunately, it is being done with impunity.

Sir, I have two other points. One is with regard to our food production. Sir, exodus from our villages is happening because there are no civic amenities in villages. If you provide civic amenities in villages, then the exodus can be stopped. When the exodus stops, then there could be good agriculture. Unless you prevent exodus from our villages, how can you have good agriculture?

(SHRI M. RAMA JOIS)

Secondly, Sir, the science says that if you want to work on the electrical power, you must use hand-gloves. There is something for our political science too. I have studied and produced a book on our political science. It says, if you want to handle the political power, you must have the hand-gloves of Dharma. You are handling the political power without Dharma and that is the reason for the rampant corruption now.

Sir, particularly, 1 appeal to the Finance Minister to consider my first point seriously. The Finance Minister is so experienced. The expression of the law in article 21 of the Constitution does not mean Executive order. This must be taken into account and the Aadhar project must be stopped forthwith. Thank you, Sir.

सुश्री सुशीला तिरिया (ओडिशा) : सर, मैं आपको धन्यवाद दूंगी और suggestions के तौर पर कुछ कहना चाहूंगी। Sir, Budget is a vast subject, लेकिन Constitution के Schedule V और Schedule VI के संदर्भ में Tribal districts के बारे में कहना चाहूंगी कि जो प्रोजेक्ट्स इधर से वहां implementation के लिए जा रहे हैं, जैसे कि "मिड डे मील" और "सबला" की स्कीम्स हैं, इन स्कीमों के लिए इतना सारा पैसा केन्द्र से दिया जा रहा है, लेकिन जब इन प्रोजेक्ट्स का प्रॉपर implementation नही होता, तब तक उस पैसे का ठीक से यूज नहीं हो सकता। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस में malnutrition बहुत जबर्दस्त ढंग से बढ़ना जा रहा है।

उपसभापति जी, National Health Mission के तहत भी malnutrition के क्षेत्र में तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। इस तरह स्वास्थ्य के कोई काम नहीं हो रहे हैं तथा एजुकेशन की क्वालिटी भी नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसा कोई माध्यम हो, जिससे शैड्यूल 5 और शैड्यूल 6 के क्षेत्रों में directly केन्द्र से कुछ deal की जा सके। वहां पर केन्द्र के जो प्रतिष्ठान हैं, वे स्थानीय सरकार की लापरवाही के कारण establish नहीं हो पा रहे हैं, उनका पैसा वापस आ रहा है, सेंट्रल स्कूल के स्कूल भी establish नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए केन्द्र को direct हस्तक्षेप करना चाहिए और वहां पर जो जमीन उपलब्ध है, उसी जमीन पर उन सरकारी प्रतिष्ठानों को बनाना चाहिए, ताकि वहां के tribal बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें।

उपसभापति जी, एक प्वाइंट मैं यह कहना चाहती हूं कि बजट में LPG और केरोसिन में tax reduction के जरिए direct subsidy देने का प्रावधान रखा गया है, उसी तरह से यह जो फूड सिक्योरिटी बिल है, इसके अंदर directly consumer के account में पैसा जमा करने का प्रावधान हो, तो उन्हें भी महसूस होगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे BPL cardholders की भलाई के लिए कुछ काम किया है। हमारे tribal क्षेत्र में जो mid-day meals दी जा रही हैं, उसमें जो food adulteration हो रहा है, उसका supervision होना चाहिए। वैसे तो state subject कहकर इस बात को टाल दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं यह कोई state subject नहीं है, they are also citizens of this country, वे लोग भी इस देश के नागरिक हैं, इसलिए उनके बच्चों को केन्द्र सरकार की मदद से सही स्वास्थ्य, सही एजुकेशन, सही कम्युनिकेशन मिलना चाहिए। मैं इस बजट का समर्थन करती हूं। आपने मुझे इस पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : Hon. Deputy Chairman, Sir, first of all, I would like to express my deep appreciation to all the hon. Members of the House and for the last three days up till now 43 members have participated in the discussion. The debate was initiated by Shri Arun Jaitley, the hon. Leader of the Opposition and I must recognise his contribution in analysing the Budget

[SHRI PRANAB MUKHERJEE]

in a wider perspective and presenting certain crucial economic issues which are to be addressed not only by the Government but also by the country as a whole. I appreciate that approach. Many distinguished Members have made their valuable suggestions. Some of the speeches I was able to listen to. For instance, on the first day I was present here. On the second day I could not do it for obvious reasons because I had to reply to the debate in the other House. Today before lunch I was present for some time, and before the reply, of course, I have come. But I have noted many of their suggestions and my colleagues, Ministers of State for Finance, who were present, have also noted their viewpoints.

Sir, while formulating the Budget, we had to keep in mind the conditions prevailing within the country and outside the country. Sometimes when we refer to the developments outside the country, some people raised their eyebrows. I do not know the reasons for that. When I refer to the crisis in the Middle East, it has a direct bearing on the farmers of this country because the Phosphatic and Potassium fertilizers, which our farmers use, almost 100 per cent, are imported from those countries.

And if there is a political uncertainty in Libya or Syria or some other countries from where these items are imported, surely it will have its bearing on us. Take the example of oil. What is our domestic production? If I remember correctly in early 80s, it was 29 million tonnes. Today we have gone up to 38-39 million tonnes. We import more than 110 to 120 million tonnes every year. Therefore, if the petroleum prices moved from 36 dollars per barrel, when this Government came to power in May 2005, to 115 dollars per barrel today, for which I had to buy throughout the year of 2011; it has the bearing on the crisis and development in the world outside India because we are not the master of determining the oil prices there. We have to meet the consequences. I am referring to these points only to highlight that in a world like this, today, we do not live in isolation. The action, reaction, developments outside the world have influence *over* us. If the Euro Zone crisis, I refer, is not for academic discussion, it is because of the hard fact. Except two months, in the calendar year of 2011, instead of inflow, there has been outflow from the investors coming from that region, banks, mutual funds, who invested in India. Because of the domestic constraints they had to withdraw it, and the problem is not yet *over.* I hope there will be a life at the end of the tunnel, but still it is not possible, and if this contagion extends its operation beyond these four countries, P.I.G.S.—Portugal, Ireland, Greece and Spain, and if it engulfs a larger economy, Mr. Deputy Chairman, Sir, I am afraid, any amount of bail out package, either by the Central Bank of Europe or by International Monetary Fund or collectively, would not be able to improve the situation. The Leader of the Opposition rightly pointed out some adventurous investment in sub-prime housing mortgage by a bank in one part of the world in USA. How quickly it transformed into a major international crisis, which is being described as the second worst crisis, after the crisis of 1930. Therefore,

these are some of the issues, constraints. What would be its impact in the future course of action? Those had to influence any Finance Minister to take decisions and formulate his Budgetary proposals. In my speech I have mentioned that I have emphasized on domestic demand driven strategy. Why? It is simply because of the fact that I cannot insulate Indian economy, and, perhaps, nobody, sitting here or sitting on the other side, can insulate the Indian economy from the influence of external sources totally. But as far as possible, if we can insulate to that extent, that would be beneficial to us.

If you look at the growth syndrome in the context of the crisis of 2008-09, you will notice, in the first two quarters of 2008-09, the quarterly growth rate was reasonably high. But, since the beginning of the third quarter, the growth rate was deeply depleted. The fourth quarter growth had further depleted. At that point of time, like many other countries, we had injected the stimulus package worth Rs. 1,86,000 crores. It was almost 3 per cent of the GDP at that point of time. It helped us to have the GDP growth at 6 per cent plus for 2008-09. And, thereafter, to recover at 8.4 per cent, in the two subsequent years, it had its price. It was because the fiscal expansion took place. More liquidity was injected into the system. It, along with the supply constraints on agriculture products, especially the food items, led to the inflationary pressure which we had to bear for almost two years. Still, we are not out of woods. That is why, when I am projecting, I am not projecting the rate which would have been ideal if the rate of inflation was 3-4 per cent. But, I am not advocating for that. I will be happy if we can maintain the rate of inflation at 6.5 per cent throughout the year, because I know the constraints. I know; I have to pay, on an average, US $ 115 per barrel of brunt crude which we refine and use. Even if it goes more than US $ 10-12 per barrel, it will be bearable and acceptable. But, the country will have to think about it seriously. If the oil prices go up to US $ 150 or 160 or 200, would the economy be in a position to bear it? Would the economy be in a position to import even the necessary requirement looking at the size of the Indian economy today? We are spending on imports to the tune of US $ 110 or 115 or 120 million. These are the issues which we cannot keep under the carpet. We shall have to address. That is why I said in my Budget Speech and also in my reply to the other House that these are the issues where the collective thinking of the entire political spectrum of the country is required, because it is not possible for any individual party or group of parties to take decision. Yes; the primary responsibility lies with the Government of the day. But, I always remember, my mandate is limited. Yes; we are leading the coalition, but not with 275 seats in the Lok Sabha. With 206 seats, we may be the single largest party. But the mandate of the electorate is quite clear. The electorate says, 'I am permitting you to lead the Government, but carry people with you, carry others with you. Your mandate is not absolute. Your mandate is limited.' In that process of carrying people with us, if it is strenuous, if it is time-consuming, I do not know, excerpt making efforts to carry others with us, whether there is any short-cut through which we can deal these issues.

[SHRI PRANAB MUKHERJEE]

Now, the question comes, what have I done? What is the credibility of the numbers that I am showing? Last year, I projected a figure of 4.6 per cent fiscal deficit. It has gone up to 5.9 per cent. So, when I am saying that it is 5.1 per cent for the current year, what is the credibility? The credibility is: I am accepting the responsibility of taking subsidies in terms of percentage of the GDP, because we shall have to do it. If the economy does not have the capacity to spend more, we shall have to do it. We cannot forget what had happened in 1990.

We cannot forget what was the level of the foreign exchange reserves in 1990-91. What happened to the credibility of the country? It is not a remote past. It was not in 50s or 60s or 70s; it was in 1990. Therefore, we will have to draw lessons from that. We will have to work out a mechanism, a strategy, with the cooperation of all, and candidly admit it that no Government—If I go tomorrow and you come and occupy that place, you will have to seek support—can function without cooperation. I would, most respectfully, like to remind this House one old event. It was in 1995. India signed WTO Agreement at Maracas. As a condition, particularly in respect of Intellectual Property Rights, we were to amend the Indian Patent Act of 1973. But Process Patent was no permitted, the Product Patent was permitted. But, as a signatory to the WTO, India had two options—either we give the exclusive market rights to the new products for ten years, or, amend the Act. I, as the Commerce Minister at that point of time, brought the Bill twice; but, I failed. My colleague, Sitaramji, is nodding. The Communist Party persistently opposed then and persistently opposed later on too. They had ideological differences. I remember there was some sort of forum, headed by Dr. Murli Manohar Joshi, a Member of this House then, and Dr. Ashok Mitra. It was a great combination of the Marxists and the BJP! Both of them opposed that and that could not be passed. Ultimately, somebody complained to the dispute settlement mechanism of the WTO. We lost a series of cases. In between, the Government changed. Mr. Arun Jaitley came here and we went there. Then, there was no scope of further appeal. Advaniji discussed with me and Dr. Manmohan Singh, who was then the Leader of the Opposition. I said that simply by accidental change of sitting does not change the validity of a proposal; whether we sit this side or whether we sit that side, that does not make any change. We supported that and necessary amendments were carried out. And, if somebody, with some curiosity, try to make a little more research, he will be surprised to find that a very nominal change was made, except the change of the name of the Member-in-charge. At that point of time, the Member-in-charge was me, Pranab Mukherjee. And, subsequently, the Member-in-charge was Mr. Murasoli Maran, who was the Commerce Minister in the initial years of NDA regime. The short point, which I am trying to derive at, is that we shall have to cooperate, we shall have to work together because we cannot go on every drop of hat to the elections to 543 Lok Sabha

constituencies, covering more than 700 million voters. It is not a fun. Therefore, we shall have to carry the Government. I must respectfully recognize that Indian political system has shown this wisdom from 1989 till date—1989 elections, 1991 elections, 1996 elections, 1998 elections, 1999 elections, 2004 elections and 2009 elections. Not even in a single election the Indian electorate gave a clear verdict, but every time gave a fractured verdict. The political parties responded to that and successfully led the coalition Governments, whether it was led by the BJP or it is led by the Congress. But the coalition Governments worked. Even between 1991 to 1996, on many issues, when Late P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister, cooperation was received from the Opposition because at that time also the Congress did not have a clear majority

Congress started with 226. After Punjab elections, there was some improvement, but it was not 275 or 273. Therefore, the measures which I am taking depend much on how we can build up the consensus amongst the political parties. As far as the domestic demand-driven strategy is concerned, the most important thing is to make investment in agriculture, because that' is an important area where we can encourage the domestic demand to grow. I have done that. Yes, I entirely agree with all the Members who have said, "Mr. Finance Minister, you have done little." Yes, I would have been happy if I had made much more allocations. If instead of stepping up the agricultural allocation to 18 per cent as compared to the last year, I had given much more, I would have been happy. But when I am stepping up the Plan allocation to 18 per cent, I could not expect more investment in areas like social sector, ICDS, drinking water and total sanitations. These are the areas which cover the rural sector and, there, the investment is much more. In agriculture, I have increased the allocation by 18 per cent and Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) by 17 per cent. When I announced the scheme 'Bringing Green Revolution in Eastern India', many people expressed their skepticism. It was said that nothing concrete and substantial will be achieved. The first year allocation was Rs.400 crores. But I am thankful to the Chief Ministers of all the Eastern region, starting from Bihar, Orissa, West Bengal, Chattisgarh, that they took personal interest. I had several interactions with the Bihar Chief Minister on this issue. Even two days before the presentation of the Budget, I had an opportunity to discuss this issue. He has also worked out a model which is working very well. An additional 7 million tonnes of rice production which has come from that sector is to substantiate that potentiality is immense. What has been the achievement for the first time? For the first time, India has produced more than 102 million tonnes of rice and it has been recognised by the Director General of Food and Agricultural Organisation, and also by the Director General of International Rice Institute of Manila. What have they stated? I would just like to quote a few words from their observations. It is a lengthy observation, but I would like to quote only a few words. Mr. Robert Zeigler is the Director General, International Rice Research Institute. He said, "The most heartening aspect of India crossing the 100 million tonnes rice production mark is that a major contribution has

[SHRI PRANAB MUKHERJEE]

been from the Eastern India." The Director General, FAO, Mr. Jose Graziano da Silva, said, "I congratulate Government's achievement of exceeding for the first time in history 100 million tonnes of rice production and 250 million tonnes of the foodgrains." Without agricultural strategy, without making investment, without providing extension services and without giving emphasis on research and development, it would not have been possible. I bow down to the efforts of the Indian farmers. I salute the Indian agricultural scientists and researchers for their constant endeavour to build India.

And, just to encourage that, I have made a very small gesture by earmarking some money for the researchers, scientists and for those who are working in different agricultural institutes. Some of the agricultural institutes are financed. I have given some small token contribution—it is quite inadequate for them—so that they can also make contribution because all the Members who have participated in the Budget discussion have touched agriculture. Some of them expressed their concern that the share of agriculture is coming down in the overall basket of GDP. I am not very much alarmed over that. But I am alarmed over the other issue. I am concerned about the other issue because though the share of agriculture is coming down, the dependence of persons on agriculture is not coming down proportionately. That should have come down. Otherwise, agriculture is going to be overburdened. When you talk of the food security, food security does not mean merely giving certain quantum of food to certain targeted groups at a pre-determined rate of price. The first and foremost condition of food security is, we must produce enough which can feed 1.2 billion people, 121 crore people. No country of the world can feed them. We shall have to feed ourselves. Those days are gone when we had to depend on imported PL-480 wheat or other types of imported foodgrains. We have come out of that stage. Even the size of the population at that time was only 350 to 450 million. Sir, I do agree with Dr. Swaminathan's recommendations. Yes, we could not implement it fully, but that does not mean that it is not worth pursuing. In our future strategy for the development of agriculture, we shall have to take note of the expert observations made by Dr. Swaminathan, and I can assure the House that I am fully aware of it.

The second aspect is an important aspect. Many a time you have expressed your concern about the wastage, leakage. Even, sometimes, the Supreme Court Benches have also made a comment on it. As I mentioned earlier, even in the last two years, the production and, simultaneously, the procurement of the foodgrains have been substantial. In 2009-10, it was 218 million tonnes, in 2010-11, it was about 245 million tonnes, and, in 2011-12, it is 250 million tonnes. Now, to have the storage facilities, we have made investments and we are encouraging investments. Even I have earmarked certain amounts from the RIDF to be spent on creating godowns, warehouses and cold-chains. Even the Viability Gap Fund, which is coming from the Government, I am extending

this facility, even lowering of interest rate, withhold tax from 20 to 5 per cent, to create cold-chain, warehousing and other activities. The total storage facility right now with the FCI and all other organizations is 47 million tonnes. By the end of 2013, by 31st December, 2013, we are going to add 15 million tonnes additionally, including 2 million tonnes' silos. I hope in the next couple of weeks, 3 million tonnes are coming. Another 5 million tonnes will be coming by 31st March, 2013, and the balance, by 31st December, 2013. In other words, by 2013, additional 15 million tonnes will be added, but, in addition to that, we are encouraging building up warehouses, building up cold chains, etc.

Even one banking facility, the agricultural credit, which you are fully aware of, in 2008, was of the order of Rs. 2,50,000 crores. This year, I announced Rs. 4,75,000 crores, and I am pretty sure this limit will be surpassed; for the next year, I have indicated Rs. 5,75,000 crores. I know that this is also not adequate. There are more than ten crore Kisan Credit Cards. We have this short-term crop loan of Rs. 3,00,000; it is not for rich farmers; it is meant substantially for the middle and poor farmers. The Interest Subvention Scheme of one per cent, which I announced in my three successive Budgets, will actually bring the rate down to four per cent, if they pay in time. I have also extended these facilities to Women Self-help Groups. I have provided additional interest subvention to help the farmers, to those farmers who would keep their produce in warehouses and, on the basis of a certificate given by the warehouse, they would get another six months' credit facility, because that is the period when if they store their products, then, prices will go up and they would get remunerative prices and, if not remunerative, at least, reasonable prices from the market. Otherwise, if he sells it immediately, then, the prices would crash and we would be seeing the type of distortion which we see many times. So, in order to generate the growth momentum, we shall have to make investment in rural infrastructure. I have made infrastructure investments. I have stepped up allocation for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana; I have stepped up allocation for AIBP; I have stepped up allocation for education. Here, I would refer to one point which was raised by the hon. Leader of the Opposition. He said that we were shifting the share of the States. Yes, I agree with him; in the three years since the scheme was introduced, the share was shifted from 65 per cent to 50 per cent. But, thereafter, from 2010-11, it has been decided that for Sarva Shiksha Abhiyan this share would be 65:35 and it has been rested there. So, the reduction from 65 to 60 to 55 to 50 has been given up. Now, it is being rested at 65:35.

And in this connection, Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to take this opportunity to share some of my perceptions about the Centre-State relations, particularly, with respect to fiscal relations because, somehow or the other, I was one of the instruments even in setting up the Sarkaria Commission in 1984. Even at that time, I was the Finance Minister and one of my decisions raised a huge controversy.

[SHRI PRANAB MUKHERJEE]

That was about the non-implementation of the full Report of the Eighth Finance Commission. Some of the State Governments, and, particularly my Leftist friends from West Bengal which did not get some 300 or 400 crores of rupees, till today, raise an accusing finger at me saying that I have deprived West Bengal and other States. Why had I deprived them? What were the conditions? The condition was "to rob Peter" to give it to somebody else; because we had actually allocated it to be given to Paul. So, 100 per cent allocation was made to the States. Now, there were variations between the interim report and the final report. I requested the then Chairman to give me the report before the presentation of the Budget, but, unfortunately, that did not happen. So, this is what had happened. But that is not the issue. The issue is, as a result of that, it was decided to set up a High-powered Committee to determine the Centre-State fiscal relations. Please remember, one important observation of the Sarkaria Commission was that from 1951 to 1983 the compound average growth rate of the State revenue and the compound average rate of growth of the Central revenue was around 17 percent.

And after devolution, whatever the formulation of the devolution was, the share of States' revenue used to be a little higher. What has been the share of devolution? Four Finance Commissions looked into it. They are the Tenth Finance Commission, the Eleventh Finance Commission, the Twelfth Finance Commission and the Thirteenth Finance Commission. In the Tenth Finance Commission, the maximum recommendation was 77.5 per cent of the income tax and 47.5 per cent of the excise duties. Customs duties were never distributed; all taxes were never distributed. From 1951 till date, thirteen Finance Commissions have been established and the devolution has varied from one Commission to other Commission. But it has never happened that all the taxes were brought together. Sometimes, customs duties were out; sometimes, a limited number of items of the Central Excise were put in the divisible pool. But the Eleventh, the Twelfth and the Thirteenth Finance Commissions have brought all the items together, determined in terms of percentage of the total tax realized. It was first 29.5 per cent. Then, it was increased topper cent. The Thirteenth Finance Commission has increased it to 30.5 per cent. If you compare the devolution, in terms of percentage, between the Twelfth and the Thirteenth Finance Commissions, you will find that it is as high as 150 per cent in respect of some States and it is not less than 96 per cent in any case. Therefore, a larger devolution is taking place. A lot of comments have been made that I have become cruel to be kind. Here, I have become cruel to myself to be kind to States. Because of my Rs.41,000 crore of duties, which I am imposing, States are going to have a share of 32 per cent. But everyone of you accused me asking why I am increasing 2 per cent excise duty and 2 per cent services taxes. Of that Rs.41,400 crore, 32 per cent will go to the States as part of the share of the devolution. And I am

to do that. But that does not mean that the position which prevailed in 80s about the States' finances is relevant today. I am happy that the States have made substantial contribution, particularly few States where the GDP growth is very high. At the same time, I am aware that some of the States are debt-stressed. Because of some historic reasons, or, because of some legacy—I am not going into that aspect—debt burden has increased substantially. I am to address that. I am to address that not globally or not on an all-India pattern, but I am to address the problem of the States concerned. Why have I kept up BRGF substantially? It is a Backward Regions Grant Fund. It is an outward Grant from the Centre to the States to help them. You have noticed that I have stepped it up substantially. Some States have used it earlier. West Bengal has got this benefit only recently; it got it only in the month of October-November.

But, Bihar got the benefit earlier, and the Chief Minister has used it very efficiently and effectively. As a result, there has been substantial development. So, I am addressing this issue. Now, how can we address the debt burden? The Finance Commission recognises that. Unfortunately, what went wrong with some of the States was that Rs. 1,22,000 crore went to debt consolidation as a result of the 12th Finance Commission's recommendation for those States who enacted the FRBM Acts early. Those, who got the benefit substantially, enacted the FRBM Acts in 2004, 2005 and 2006 when the 12th Finance Commission's recommendations helped them for debt consolidation and also helped them to share a part of the Finance Ministry's debt waiver to the extent of Rs. 20,000 crore. But those, who came late and got the FRBM Acts enacted only in early 2011, could not naturally get the benefit of that. So, these are the problems. But, I am addressing these problems. I have appointed a small group to look into, particularly, three States which have been referred to in the observations of the 13th Finance Commission - Punjab, Kerala and West Bengal. I am asking them also to look into these aspects in their entirety and when the 14th Finance Commission will be set in, naturally, they will take care of it. But, what can be done in between the 14th and the 13th Finance Commissions? I am going to look into it. It would be our effort to build up a healthy relationship.

In this connection, I would like to make only two points, and one point, on which I have already made an announcement in the other House. I would not like to elaborate on it. And, I am readily accepting one suggestion which has come on the floor. I think, Mr. N.K. Singh has suggested that as the Eastern India is contributing in the context of second Green Revolution, whether I can institute a Committee of the Chief Ministers, or Chief Ministers' nominees, of Eastern India to give a momentum to this idea of the second Green Revolution. It is a worth considering suggestion and I would like to explore the possibilities of setting up such groups. It will consist of the Chief Ministers of Chhattisgarh, Odisha, Bihar, West Bengal, Assam. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal) : Will this Committee be with money or without money?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Of course, this Committee will be with money. I have given money. I always give money. And, I am one of the strong advocates of transferring the Centrally-sponsored schemes with money and it should be reduced because the States know where the problems are. But, at the same time, there should be some uniformity. It is a federal finance, and the federal finance should not become weak. If the States' finances become weak, they will look at the federal Finance Minister. But, at whom will the federal Finance Minister look–the Managing Director, IMF, or the Chairman, World Bank? None of them would be able to bail out India. It is of a huge size. Therefore, we shall have to strike a balance. And, I am happy. Everyday, I take the States' 14-day treasury bills investment. Earlier, I used to say that out of 28 States, hardly any State had surplus. Today, there is hardly any State which does not have a surplus, and the surplus varies between Rs.95,000 crore to Rs.1,05,000 crore and Rs.1,10,000 crore. It is a good sign. Though I have not been able to fully analyse all the States' budgets, but some of those who have done it, I have found that quite encouraging efforts are being made to achieve higher growth. By enacting the FRBM Acts, they are bringing the discipline. But, in the tax-GSDP ratio also, there should be some uniformity. Some of the good States, having high per capita income, having high growth, are bringing tax-GSDP ratio to around 7, 8 and 9 per cent.

What percentage would be there, I leave it to the States. But there should be some proportion between the State GSDP and the State Tax Ratio. In this connection, I would also like to mention that some skepticism has been expressed about the GST and the compensation of the Central Sales Tax. So far as the history of Central Sales Tax is concerned, it was agreed upon between the Empowered Committee of State Finance Ministers and the Ministry of Finance that we will bring down the Central Sales Tax from 4 per cent to 3 per cent, 3 per cent to 2 per cent, 2 per cent to 1 per cent, and, from 1 per cent to zero, over a period of four years, starting from 2007-08. And, for that, if there is any compensation required to be paid, then, that compensation will have to be paid by the Central Government.

In 2007-08, we brought it down from 4 per cent to 3 per cent, and, we paid the compensation. In 2008-09, it was brought down from 3 per cent to 2 per cent, and, the compensation was paid. Then, I became the Finance Minister, and, I took over the finance. In 2009-10, I was advised by the Empowered Committee of State Finance Ministers not to bring it down further because there was economic crisis. Three items were tobacco, textiles, and, sugar, and, the condition was that the States will increase the VAT from the level which prevailed in 2007-08. Certain other technicalities were also to be observed by both sides. Both sides did it. Then, thereafter, another question arose. The compensation went on increasing but there was no visibility of making

5.00 P.M.

GST available. The idea was that GST will be implemented from 2010-11, and, once, GST will be implemented, all these taxes will be subsumed there. Sir, 2010-11; 2011-12; and, 2012-13 is going to be over. It is not visible. Therefore, I told, at the end of the tunnel, there must be light, the visibility of the light, otherwise, how can it work out.

After all, in between, the States have also increased the VAT, which was four per cent, and, which has gone, in some States, to six per cent. The arrangement was that it would be computed to determine the compensation for the States. Each State furnishes its own list after making the permutation and combination, and, after making the due computation, the quantum of the compensation to be paid is being determined.

I have received a letter from the Chairman of the Empowered Committee of the State Finance Ministers. I have not closed the issue. Surely, I will see into it, and, then, I will discuss and find out a workable solution, through which we can proceed further.

Two positive developments have taken place with regard to GST. I am happy to share it with you. The GST Network is in place. There has been criticism. I am not going into that aspect but they are doing good job. I am also not going into the dispute of the Standing Committee's rejection of a Bill, because to reject a Bill is the inherent right of the House, and, not of a part of the House, which is reflected by the Standing Committee. But I am not going into that debate. Many decisions have been taken through executive orders, and, thereafter, they have been translated into legislation. We wanted to give the legislative backing to it. What is Pension Fund, what is New Pension Scheme? The New Pension Scheme was introduced from 1st of January, 2004.

It is operational. Huge amount of money has been collected from the contributors of the New Pension Scheme, and that is being managed by the fund managers. Till now the legislation has not been passed from 2004 onwards. But that does not mean that the Executive does not have the power to take a decision and to put it into operation through Executive orders. Accountability will be there; CAG will be there; audit will be there, whether it will be backed by legislative measures or whether it will be backed by Executive decision. And, please remember, the Standing Committee is a part of the House. Rejection of the Bill is the inherent right of the House as a whole, not the Standing Committee. The Standing Committee can make recommendation. With due respect, I will examine the recommendations of the Standing Committee, and, if I can, I will definitely make the necessary amendments and bring it in the next Bill. But that does not prevent to carry on the action. In that case, what will I do with my Pension Fund where the contributors are paying? Law has not been passed. Law could not be even introduced. In the other House, it was introduced. My Leftist friends opposed it, but with the support of the BJP, we could get it introduced. It is under the consideration of the Standing Committee. But that does not mean, from 2004 January, I shall not

[SHRI PRANAB MUKHERJEE]

operate the Pension Fund. It will be a preposterous suggestion. What should I do with this huge amount of money? Executive is accountable to the legislature. Where it wants to give the legislative backing, it depends on the Executive. Certain things are there where legislation should be absolutely necessary. Therefore, let us not go into that debate right now. My short point is that for CST, the Members who have expressed their concern, I can assure them we are going to look into that aspect. I have received the communication from the Chairman of the Empowered Committee of the State Finance Ministers.

The last point on which I would like to make a comment is, as I mentioned in the other House, I have received the representations from various quarters, including my party men, my Cabinet colleagues, other political leaders, the Leader of the Opposition also mentioned this and suggested me to re-consider it. I am re-considering about the proposed taxes on the jewellers. As it will have to be done through the legislative route, I am not exactly going to indicate what would be the modality. For that, you shall have to wait till the Finance Bill is being brought for your consideration and approval. The short point which I am trying to say is, I repeated it when I met them, up to rupees five crore turnover, no question of bringing them within the tax limit. Whether inspector ray will go or not, self-declaration that my turnover is rupees five crore, will be the final say. There will be no further scrutiny. In addition to that, there are certain other problems like if somebody buys gold of rupees two lakhs in cash, whether he will have to give PAN Card or not, that is an issue we are examining and at the appropriate time, I will come forward.

The last point is, please do not insist on deduction of import duty on gold. Last year, only up to the month of November, the country had to spend precious 46 billion US dollars for importing gold. You cannot afford to have it next to petroleum. Not capital goods, not raw materials, not intermediate products, but gold import was of 46 billion dollars from April to November when the import Bill of petroleum and petroleum products was roughly about 71-72 billion dollars. Fortunately, I could take the risk a little bit because the difference between international price and domestic price of gold has come closer. There was a time in 70s when it was a constant fear of us. Difference between the domestic gold and international gold price was huge.

We have to keep this in mind. The other day while replying to a question, I mentioned that our indigenous gold production is quite insignificant. It is only two metric ton. Look at our gold bearing ore. Per ton ore, you have hardly 14-16 grams of gold. And what is the cost of extraction? There are Kolar gold mines and Hutti gold mines. They are very costly. Some gold we get after refining silver or zinc. This is a by-product. But the quantum is very small. Though the craze for gold is there, reduction in import duty is not possible. But I am going to look into the other aspects of it.

With these words, Sir, once again, I express my deep appreciation of all the hon. Members who have made their valuable contribution. Thank you, Sir.

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : आपने जो सोना व्यापारी के सम्बन्ध में कहा है, उनकी ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Thank you. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal) : Sir, I have a small clarification.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : A detailed reply has been given.

SHRI TAPAN KUMAR SEN : Sir, while I fully appreciate his explanation on the contagious effect of the global crises on our economy, why should we not consider also to put a cap, to peg it along with pegging the subsidy, if not instead of, and have a target on increasingly increasing revenue raised but not collected which is ...(*Interruptions*)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I would clarify it. ...(*Interruptions*)... Just give me one second. ...(*Interruptions*)... Sir, there are two types of issues which are coming. One is that we are raising revenue but not realising it. I am telling you the case of income tax. We have raised revenue, but we are not realising it. I will tell you about two cases. One is of Harshad Mehta. And the other one is of Hasan Ali. They are *sub judice.* Both the cases have been pending for years in the court. No visible assets are available. Harshad Mehta died. His successors are fighting the case. If you take into account these two outstanding cases, you will find that it will be more than 60 per cent of the total amount shown in the Budget. And, every year, 14 per cent interest is being added to it, but not a single rupee has been realised. Next year, you will find the same amount with 14 per cent interest added to it. So, I am asking for an appropriate committee to look into it. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN : You keep the Harshad Mehta case apart. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Let me complete. ...(*Interruptions*)... Second question is this. I raise the demand. The assessee moves the court. It moves the appellate stage and contests the demand. As per the existing law, I have to show revenue raised, but revenue not realised. There is no way. It may happen that in the appeal I may lose the case. If I lose the case, then it will be deducted. But till then, we have to do it. These are legal issues.

In respect of indirect taxes, and in respect of direct taxes also, it is substantially because of the concessions that we are giving. There is import duty concession. There is excise duty concession. All the concessions, which we are giving, are going to fill in the growth. They are coming into that. ...(*Interruptions*)... In indirect taxes, I talked

[SHRI PRANAB MUKHERJEE]

about revenue raised. ...(*Interruptions*)... Revenue foregone is what we are giving and which should have been realised. But there are exemptions. That is the revenue foregone.

So these are the technicalities. But, I do feel that some legal clarifications are required and I will do so. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Okay. Now. ...(*Interruptions*)...What is this?

श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन : सर, ड्यूटी rollback के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई indication नहीं दिया है। ...**(व्यवधान)**... ज्वैलर्स की strike पूरे देश में अभी भी जारी है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI PIYUSH GOYAL (Maharashtra) : Sir, I had raised the issue of service tax. ...(*Interruptions*)...

GOVERNMENT BILLS - ***Returned***

The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2012
and
The Appropriation Bill, 2012
and
The Appropriation (No. 2) Bill, 2012

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : Sir, I move:

That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2012-13, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also move:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2011-12, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also move:

That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2010 in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I shall now put the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2012 to vote. The question is: